वर्ष: 3 । अंक: 225 | जयपुर, बुधवार, 24 जुलाई, 2024 । श्रावण, कृष्ण पक्ष-तृतीया, विसं 2081 | पृष्ठ: 10 | मूल्य: 2.00

दैनिक हिन्दी अख़बार

सच बेधड़क

www.sachbedhadak.com | twitter.com/sachbedhadak | facebook.com/sachbedhadak
YouTube: youtube.com/@sachbedhadak | Instagram: instagram.com/sach_bedhadak

UNION BUDGET 2024-2025

75 हजार कर दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन

- बजट में 9 प्रायोरिटी... 4 वर्ग पर फोकस, थीम में 4 लक्ष्य
- इनकम टैक्स स्लैब में किया बदलाव...

करदाताओं को 17,500₹ की बचत

बेधड़क। नई दिल्ली

मोदी 3.0 सरकार का पहला आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर रिटर्न में स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया है। इसके अलावा 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख तक 20 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

वित्त मंत्री द्वारा पेश केंद्रीय बजट 2024 का फोकस चार वर्गों गरीब, महिला, युवा और किसान पर रहा, जबकि बजट थीम रोजगार, स्किलिंग, लघु उद्योग, मिडल क्लास पर केंद्रित है। वित्त मंत्री ने बजट की 9 बड़ी प्राथमिकताओं का उल्लेख किया, जिनमें कृषि में उत्पादकता, नौकरियां, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, विनिर्माण ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और अनुसंधान और अगली पीढ़ी में सुधार प्रमुख है।

इससे पहले बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत प्रगति की राह पर बढ़ रहा है। भारत की महंगाई कम और स्थिर है। मंहगाई को चार प्रतिशत से कम पर लाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन देने पर काम हो रहा है। पीएम गरीब कल्याण को पांच साल के बढ़ाया गया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया

प्रदेश को ज्यादा पैसा देने का ऐलान

केंद्र से राजस्थान को इस बार टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में 73,504 करोड़ रुपए मिलेंगे। सीतारमण की ओर से पेश बजट में स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में यह जानकारी दी गई है। पिछले वित्त वर्ष में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को 66,556 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस साल इस राशि में करीब 7 हजार करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी 6.026 प्रतिशत है।

प्रदेश का 922 करोड़ का महत्वाकांक्षी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट मंजूर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से केंद्रीय बजट में प्रदेश के जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। ये 1578 एकड़ जमीन में विकसित किया जाएगा। इस पर 922 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना भी जारी कर दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी JPMIA को लेकर केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखे थे। राज्य सरकार ने अपने बजट में इस प्रोजेक्ट के वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 275 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जेपीएमआईए को दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) के पास विकसित किया जा रहा है।

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव

ओल्ड स्लैब	पुरानी दर	नया स्लैब	नई दर
0-3 लाख	0%	0-3 लाख	0%
3-6 लाख	5%	3-7 लाख	5%
6-9 लाख	10%	7-10 लाख	10%
9-12 लाख	15%	10-12 लाख	15%
12-15 लाख	20%	12-15 लाख	20%
15 लाख+	30%	15 लाख+	30%

रोज़गार, हुनर और युवाओं पर फोकस है मोदी 3,0 का पहला बजट

बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिसका लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। हमारी सरकार का पूरा फोकस रोज़गार, हुनर और युवाओं पर है। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि, इस समय देश में मुद्रास्फीति फिलहाल 3.1 फीसदी पर है। इस साल 1.48 लाख करोड़ शिक्षा और रोजगार के लिए खर्च करने का प्रस्ताव है।

'बही-खाता' शैली की थैली में लिपटा डिजिटल बजट लेकर संसद पहुंची

लोकसभा में सातवां बजट पेश कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण को 'बही-खाता' शैली की थैली में लिपटा एक डिजिटल टैबलेट रखा। टैबलेट को ब्रीफकेस के बजाय एक लाल कवर के अंदर रखा गया था जिस पर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक बना था।

पेज 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भी देखें

चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद

चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को भी कागज रहित प्रारूप में पेश कर करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में सोमवार को पेश आर्थिक समीक्षा में बताया था कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 6.5 से सात प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में अर्थव्यवस्था में उत्साहजनक प्रगति के संकेत मिले की बात कही गई है। संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश करने से पहले बजट को मंजूरी देने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की संसद में बैठक हुई है। इस बैठक में केंद्रीय बजट को मंजूरी दी गई है और सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को लोकसभा में पेश किया।

NDA	डिफेंस बजट पर खर्च
2014	13.15%
2015	12.61%
2016	12.56%
2017	12.91%
2018	11.62%
2019	10.96%
2020	15.50%
2021	13.70%
2022	13.30%
2023	13.20%

मुद्रा योजना: 20 लाख तक लोन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी यानी 20 लाख रुपए की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को 'इंटर्नशिप' के अवसर देने के लिए योजना शुरू करेगी।

बजट 2024 की 9 प्राथमिकताएं

- कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
- रोजगार और कौशल
- बेहतर मानव संसाधन, सामाजिक न्याय
- मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज
- शहरी विकास
- ऊर्जा सुरक्षा
- इंफ्रास्ट्रक्चर
- इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट
- अगली पीढ़ी के सुधार

किस क्षेत्र में कितना खर्च

क्षेत्र	करोड़ रुपए
रक्षा	4,54,773
ग्रामीण विका	2,65,808
कृषि	1,51,851
गृह	1,50,983
शिक्षा	1,25,638
स्वास्थ्य	89,287

दही का शुभ शगुन

बजट पर बोल...

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। केंद्रीय वित्त मंत्री को शुभकामनाएं।

-राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यह बजट नए मध्यम वर्ग के सशक्तीकरण के लिए है। युवाओं को इस बजट से असीमित अवसर मिलेंगे। शिक्षा और कौशल को नया आयाम मिलेगा। यह बजट नए मध्यम वर्ग को ताकत देगा। बजट महिलाओं, छोटे कारोबारियों और एमएसएमई को मदद करेगा।।

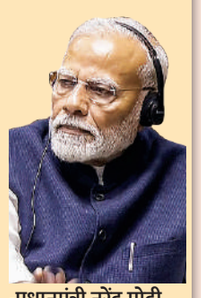

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

आम बजट को दूरदर्शी, जनहितैषी, विकासोन्मुखी है। यह न केवल भारत के उद्देश्य, उम्मीद और आशावाद की नई भावना का उदाहरण है, बल्कि उन्हें मजबूत भी करता है। भारत के युवाओं, महिलाओं और किसानों की शक्ति का उपयोग करते हुए यह बजट रोजगार और अवसरों के एक नए युग की शुरुआत कर एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने के मार्ग पर राष्ट्र की गति को बढ़ावा देता है।

-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

मोदी कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय बजट को मिली मंजूरी

संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश करने से पहले बजट को मंजूरी देने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की संसद में बैठक हुई है। इस बैठक में केंद्रीय बजट को मंजूरी दी गई है और सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को लोकसभा में पेश किया।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय बजट को सराहा

बजट में विकसित भारत 2047 की रूपरेखा तैयार: भजनलाल शर्मा

- गरीब, महिला, युवा और किसान के लिए क्रांतिकारी बजट
- कर दरों में छूट से मध्यम वर्ग तथा वेतनभोगियों को राहत
- 'आपणो अग्रणी राजस्थान' के संकल्प को मिलेगी मजबूती

बेधड़क | जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का प्रभावी रोडमैप इस बजट में तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, नवाचार, ऊर्जा, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे सहित 9 प्राथमिकताओं के साथ पेश इस बजट से भारत का विश्व की पांचवीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह बजट 140 करोड़ देशवासियों एवं 8 करोड़ राजस्थानियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला साबित होगा।

युवा, महिला, किसान और गांव-गरीब का बजट

सभी के जीवन में आएगा सकारात्मक बदलाव

शर्मा ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि इससे प्रत्येक भारतीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब, युवा, महिला, किसान सहित सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। इस बजट में गरीबों को संबल दिया गया है, मध्यम वर्ग को मजबूत किया गया है तथा देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करने का मंत्र दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए, महिला सशक्तीकरण को गति देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए, कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख 52 हजार करोड़ रुपए तथा ग्रामीण विकास के लिए 2 लाख 66 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान विकास की नई इबारत लिखेगा। मजबूत आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बजट में जीडीपी के 3.4 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

मध्यम वर्ग और वेतनभोगियों को राहत

शर्मा ने कहा कि बजट में गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ गरीबों और मध्यम वर्ग का घर का सपना पूरा होगा। बजट में नई कर प्रणाली के अंतर्गत आयकर में छूट, मानक कटौती की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए करने जैसे प्रावधान कर मध्यम वर्ग और वेतनभोगियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है।

कैंसर की दवा सस्ती... अच्छी राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा शुल्क की दरों में कमी किए जाने से कैंसर की दवाइयों, मोबाइल फोन, सोलर सैल और पैनलों की लागत में कमी आएगी। केन्द्रीय बजट की इन सभी घोषणाओं से 'आपणो अग्रणी राजस्थान' के संकल्प को मजबूती मिलेगी और विकसित भारत-विकसित राजस्थान का लक्ष्य प्राप्त होगा।

मोदी 3.0 का पहला बजट: कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान

कृषि सेक्टर का बजट 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ा

बेधड़क। नई दिल्ली

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी 3.0 के केंद्रीय बजट 2024-25 को लोकसभा में पेश किया। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया। सीतारमण ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि अभी भी शानदार अपवाद बनी हुई है। ये आने वाले साल में भी ऐसी ही रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है, जो चार फीसदी के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।

सीतारमण ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें चार अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50 फीसदी मार्जिन के वादे को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सरकारी की नौ प्राथमिकताएं हैं, जिनमें खेती में उत्पादकता में सुधार भी शामिल है। वित्त मंत्री ने अपने 7वें बजट में किसानों को कई तोहफे दिए हैं। मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 21.6 फीसदी यानी 25 हजार करोड़ रुपए का बजट बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने किसान और कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है, ये 6,000 रुपए ही रहेगी।

एक करोड़ किसानों को कराएंगे प्राकृतिक खेती

वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि रिसर्च में सुधारों पर काम करेंगे। अगले एक साल में एक करोड़ किसान नेचुरल फॉर्मिंग से जुड़ेंगे। दाल और दलहन मामले में आत्मनिर्भरता और इनके प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे। सरसों, मूंगफली, सनफ्लॉवर और सोयाबीन जैसी फसलों पर फोकस रहेगा। सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे। इनके स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे। ग्राम पंचायत और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के जरिए इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। 10,000 नीड-बेस्ड बायो-इनपुट सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे।

किसानों के लिए सरकार का खुला पिटारा

- देश के 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण होगा
- पांच राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे
- रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार होगी
- प्राकृतिक खेती के लिए एक करोड़ किसानों को किया जाएगा समर्थन
- 10 हजार जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे

पांच राज्यों में जारी किए जाएंगे नए किसान क्रेडिट कार्ड

किसानों की मदद के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नाबार्ड के जरिए किसानों को मदद दी जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर काम होगा। किसान की पैदावार को मौसम के असर से बचाने पर काम किया जाएगा। सरकार ने बताया कि 32 फसलों की 109 नई किस्में लाई जाएंगी, जो मौसम के अनुकूल होंगी।

MSP पर कोई घोषणा नहीं

बजट में किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई, वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है। ये 6,000 रुपए ही रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने एक महीने पहले लगभग सभी मुख्य फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी की घोषणा की थी। साथ ही किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि में भी इजाफा नहीं किया गया।

सब्जियों की सप्लाई चेन को करेंगे मजबूत

सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए फार्मर-प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देंगे। इनके कलेक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे। राज्यों के साथ पार्टनरशिप के तहत सरकार 3 सालों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) बनाने पर काम करेंगे। इसके साथ ही करोड़ों किसानों और उनकी जमीन की डिटेल्स को किसान और लैंड रजिस्ट्री में लाया जाएगा। इसके अलावा झींगा उत्पादन करने वालों की मदद के लिए सरकार ब्रीडिंग सेंटरों का नेटवर्क बनाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। उनकी फार्मिंग, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के लिए नाबार्ड के जरिए फाइनेंसिंग सुविधा दी जाएगी।

किसानों के लिए ये भी...

- 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।
- 32 फसलों के लिए 109 किस्में करेगी लॉन्च।
- 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।
- राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

भूमि रजिस्ट्रेशन दफ्तर बनाए जाएंगे

वित्त मंत्री ने बजट 2024 भाषण में कहा कि भूमि सुधार की दिशा में बढ़ते हुए शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड का जीआईएस मैपिंग के साथ डिजीटलीकरण किया जाएगा। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भू-प्रशासन, शहरी नियोजन, उपयोग और भवनों से संबंधित उप-नियम में सुधार का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जमीनों को एक यूनीक भूखंड पहचान संख्या दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रजिस्ट्रेशन कार्यालय बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि सुधारों को लागू करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी। केंद्र सरकार राज्यों को इन सुधारों को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए वित्तीय सहायता भी मुहैया कराएगी।

बजट पर बयान

विकसित भारत की कल्पना से सराबोर

राज्यवर्धन सिंह राठौड़
उद्योग मंत्री

बजट विकसित भारत के लिए भाजपा के विचारधारा को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। अंत्योदय के विचारधारा को ध्यान में रखते हुए, गरीब, महिला, युवा और किसान सहित हर वर्ग को मजबूती देने का काम इस बजट में दिखाई दिया है। ये बजट युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर के लिए तैयार किया गया है। एंप्लॉयमेंट जेनरेशन के ऊपर, स्किलिंग पर किसान और एग्रीकल्चर के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट खर्च हो रहा है। बजट में साधारण परिवारों के लिए इनकम टैक्स में छूट दी गई। अर्बन डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया गया। यूथ और एम्प्लॉयमेंट पर खासतौर से फोकस दिया गया। इसके साथ ईपीएफओ के माध्यम से उसे ट्रैक करने का काम किया जाएगा। युवाओं को आर्थिक मदद देने का काम इस बजट के जरिए किया जाएगा। मुद्रा लोन के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए युवाओं को आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है।

बजट में 2047 का विजन

इस बजट को 2024 का नहीं माने ये 2047 का विजन है। युवा, महिला, किसान और गरीब को इस बजट में शामिल किया है, बहुत अच्छा बजट पेश किया है। प्रदेश और देश में बजट की तारीफ की जा रही है। विपक्ष सिर्फ कमी निकालने का काम करते हैं, उनकी आदत है कमी निकालने की।

केके विश्नोई, उद्योग राज्यमंत्री

ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बजट

राजेंद्र राठौड़
वरिष्ठ भाजपा नेता

भारतीय अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाले इस बजट में सरकार का फोकस गरीब, महिला, किसान और युवा सहित प्रत्येक वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में है। बजट में 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूल मंत्र के साथ प्रत्येक वर्ग के लिए घोषणाएं की गई हैं। इससे देश के विकास को गति मिल सकेगी और हमारा देश वर्ष 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने में सक्षम बन सकेगा। बजट में देश की आधारभूत संरचनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए पूंजीगत व्यय में 11,11,111 करोड़ की विशाल राशि का प्रावधान किया गया है जो हमारी जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा, वहीं राज्यों को उनकी अवसंरचना निवेश में सहायता करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण का प्रावधान किया गया है।

अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस बजट

- सीमा सुरक्षा और घरेलू उत्पादों पर दिया जोर
- पिछले साल से 68 हजार करोड़ रुपए बढ़ा डिफेंस बजट

रक्षा क्षेत्र में और मजबूत होगा भारत

बेधड़क। नई दिल्ली

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार अपने बजट का 12.9 फीसदी हिस्सा डिफेंस के लिए दिया है, लेकिन यह अंतरिम बजट से काफी कम कर दिया गया है। इस बार रक्षा बजट के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, जबकि अंतरिम बजट में यह 6,21,541 करोड़ रुपए का था। पिछले साल की तुलना में यह बजट मात्र 4.72 फीसदी बढ़ाया गया है। पिछले साल का रक्षा बजट 5.93 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा था। वित्तमंत्री ने इस रक्षा बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपए का ऐलान सिर्फ इसलिए किया है, ताकि आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की कंपनियों से रक्षा की खरीद-फरोख्त हो पाए। उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। सीमा की सुरक्षा के लिए सड़कों का निर्माण जरूरी है, इसलिए इस बार बजट में बॉर्डर रोड्स के बजट में 30 फीसदी का इजाफा किया गया है। इसके लिए 6500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। डिफेंस स्टार्टअप्स के लिए iDEX स्कीम के तहत 518 करोड़ रुपयों का ऐलान किया गया है, ताकि नए हथियार और तकनीक विकसित किए जा सकें। अगर पिछले साल के रक्षा बजट से तुलना करें तो इस साल रक्षा बजट में 68,834 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि साल 2022-23 में यह बजट 5.25 लाख करोड़ रुपयों से थोड़ा ज्यादा था। इस बार के बजट का 27.67 फीसदी हिस्सा कैपिटल एक्वीजिशन में यानी 1.72 लाख करोड़ रुपए।

अंतरिम बजट के बाद की गई कटौती

वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 4.54 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे पहले फरवरी में आए अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र को 6.21 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया था यानी चार महीने पहले आए अंतरिम बजट की तुलना में अब पूर्ण बजट में रक्षा क्षेत्र का आवंटन 1.67 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब डिफेंस सेक्टर के बजट में इस तरह की कटौती हुई है।

लगातार बढ़ रहा था रक्षा क्षेत्र पर खर्च

इससे पहले मोदी सरकार के कार्यकाल में रक्षा क्षेत्र का बजट लगातार बढ़ता गया था। इस बार के बजट से पहले पिछले चार साल में रक्षा बजट का आकार लगभग 30 फीसदी बढ़ा था। साल 2020 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए सरकार ने 4.71 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। उसके बाद 2021 के बजट में रक्षा क्षेत्र के खर्च को बढ़ाकर 4.78 लाख करोड़ रुपए किया गया था।

4 साल में सबसे कम हुआ रक्षा बजट

साल 2022 के बजट में पहली बार रक्षा बजट का आकर 5 लाख करोड़ रुपए के पार निकला था और 5.25 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया था, वहीं पिछले साल यानी 2023 के बजट में रक्षा क्षेत्र को मोदी सरकार ने 5.94 लाख करोड़ रुपए दिया था। चार महीने पहले आए अंतरिम बजट में तो रक्षा बजट का साइज बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया था, हालांकि इस बार रक्षा क्षेत्र को 4.54 लाख करोड़ रुपये मिले हैं, जो 4 साल में सबसे कम हैं। साल 2019 में रक्षा क्षेत्र को इससे भी कम 3.19 लाख करोड़ रुपए मिले थे।

रक्षा पेंशन के लिए 141.205 करोड़

केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप, नवाचार और छोटी इकाइयों को तकनीकी मदद के लिए आईडेक्स योजना के तहत 518 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट में रक्षा पेंशन मद में 141.205 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह आम बजट देश को उत्कृष्ट, समृद्ध और आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि समावेशी और तेज गति वाले विकास की दृष्टि से यह बजट भारत के आर्थिक परिवर्तन को गति देगा। बता दें कि अर्द्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ को 2023-24 में 31,389.04 करोड़ के संशोधित अनुमान से बढ़कर 31,543.20 करोड़ रुपये मिले। बीएसएफ को 25,472.44 करोड़ रुपए (2023-24 में 25,038.68 करोड़) और सीआईएसएफ को 14,331.89 करोड़ रुपए (2023-24 में 12,929.85 करोड़) मिले हैं।

रक्षा बजट के चार पार्ट

रक्षा बजट को 4 भागों में बांटा गया है, इनमें पहला पार्ट है सिविल का, दूसरा हिस्सा है रेवेन्यू, तीसरा कैपिटल एक्सपैंडीचर और चौथा पेंशन। इसमें सिविल से बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन, ट्रिब्यूनल समेत सड़क व अन्य डेवलपमेंट के काम होते हैं, इसके लिए 25 हजार 963 करोड़ रुपए रखे गए हैं। रेवेन्यू बजट से रक्षा क्षेत्र में सैलरी बांटी जाती है। इसके लिए 2 लाख 82 हजार 772 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा कैपिटल एक्सपैंडीचर से हथियार और अन्य जरूरी उपकरण खरीदे जाते हैं, जिसके लिए बजट में 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं। तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा होता है पेंशन, इसके लिए बजट में 1 लाख 41 हजार 205 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मजबूत होंगी हमारी सेनाएं

किसी भी देश की सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके हथियार, फाइटर प्लेन और गोला बारूद होते हैं। रक्षा बजट में हथियार और उपकरण खरीदने के लिए सरकार ने 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस पैसे से एयरक्राफ्ट और एयरोइंजन उपकरण खरीदे जाएंगे। इसके अलावा हैवी और मीडियम व्हीकल, अन्य हथियार और गोला बारूद खरीदे जाएंगे। इसके अलावा अन्य तकनीकी उपकरणों से भी सेना को सुसज्जित किए जाने की योजना है। सेना के लिए स्पेशल रेलवे वैगन खरीदे जाएंगे। वी के लिए भी सरकार इस बजट से एयरक्राफ्ट और अन्य उपकरण खरीदेगी। इसके अलावा नेवल फ्लीट को मजबूत किया जाएगा और अन्य नेवल डॉकयार्ड प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। एयरफोर्स के लिए भी एयरक्राफ्ट, हैवी व्हीकल और अन्य उपकरण खरीदे जाने की योजना है।

आत्मनिर्भर बनेगी सेना

डिफेंस बजट में सेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई प्रावधान हैं। इनमें तीनों सेनाओं के लिए हथियारों और उपकरणों के निर्माण के लिए कई परियोजनाओं की तैयारी की गई है। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यमों में भी निवेश के लिए सरकार तैयार है। इससे पहले अंतरिम बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि डिफेंस सेक्टर के लिए डीप टेक टेक्नोलॉजी मजबूत की जाएगी। इसका मकसद हथियारों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अलावा रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और क्वांटम कम्प्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में रिसर्च भी की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा- पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान...

ओडिशा घूमने के लिहाज से खूबसूरत राज्य, पर्यटकों को लुभाएंगे

बेधड़क. *नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने ओडिशा के पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाओं की घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी अवसर खुलेंगे। हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं।*

कोणार्क सूर्य मंदिर यहां... पुरी में विराजे हैं जगन्नाथ

यहां प्रचीन कोणार्क सूर्य मंदिर को देखने के लिए साल भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। ओडिशा की राजधानी के रूप में जाना जाने वाला यह शहर लंबे समय तक राजा शिशुपाल के शासन का हिस्सा था, जिस वजह से यहां का इतिहास, विरासत और शहरीकरण उत्कृष्ट नजर आता है। इसके अलावा, यहां का वन्यजीव अभयारण्य, गुफाएं आदि भी भव्य चीजें समेटे हैं। धौली हिल्स, उदयगिरि और खंडगिरी गुफाएं, रत्नागिरी बौद्ध उत्खनन, बिंदु सरोवर, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क यहां के मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं। यहां पुरी में स्थित, जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ को समर्पित है। यह प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव का स्थल भी है। यह मंदिर चार धाम यात्रा में भी शामिल है।

धार्मिक के साथ ही अन्य खूबसूरत लोकेशन

ओडिशा घूमने के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत राज्य है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर को मंदिरों की नगरी कही जाती है, लेकिन यहां धार्मिक स्थलों के अलावा भी कई खूबसूरत जगह देखने लायक हैं। पुरी बीच, चिल्का झील और पक्षी अभयारण्य और गुंडिचा प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। कटक महानदी नदी डेल्टा की नोक पर स्थित शहर है, जो पहले ओडिशा की राजधानी हुआ करता था। महानदी बैराज, बाराबती का किला, भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, अंसुपा झील, सिंगनाथ और भट्टारिका के मंदिर यहां के प्रमुख आकर्षण का केंद्र हैं। धोली हिल्स दया नदी के तट पर स्थित है, इसे आमतौर पर धौली शांति स्तूप के रूप में जाना जाता है। यह पर्यटकों के बीच आकर्षण का केन्द्र है। यहां अशोक स्तंभ, बुद्ध प्रतिमा पार्क और कई चीजें देखने लायक हैं। लिंगराज यह भुवनेश्वर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान शिव के अलावा विष्णु की भी पूजा की जाती है। देश के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक पारादीप (जगतसिंहपुर जिले) खूबसूरत समुद्र तटों, घने जंगल, झरनों और किलों से भरा पड़ा है। पारादीप, महानदी और बंगाल की खाड़ी के मुहाने के इस खूबसूरत संगम पर बसा है, जिस वजह से यहां विशाल जहाजों और अन्य समुद्री गतिविधियों का नजारा देखा जा सकता है।

नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में किया जाएगा विकसित

महाबोधि-विष्णुपद में बनेंगे काशी विश्वनाथ जैसे कॉरिडोर

बेधड़क. नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को घोषणा की कि बिहार के गया में स्थित विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और बोधगया में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के व्यापक विकास को सरकार समर्थन देगी, ताकि उन्हें 'विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थल' बनाया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि ये गलियारे सफल काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारे की तर्ज पर बनाए जाएंगे। विष्णुपद मंदिर फल्गू नदी के किनारे स्थित सबसे प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है, वहीं महाबोधि मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि पर्यटन हमेशा हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयासों से रोजगार सृजन होगा, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा अन्य क्षेत्रों के लिए आर्थिक अवसर खुलेंगे।' उन्होंने कहा कि बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के व्यापक विकास को सहयोग दिया जाएगा और इन्हें सफल काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के प्रारूप पर विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थलों में तब्दील किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बिहार के राजगीर तथा नालंदा में विकास की घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि राजगीर हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है। जैन मंदिर परिसर में 20वें तीर्थंकर मुनिसुव्रत का प्राचीन मंदिर है। सप्तऋषि या सात गर्म झरने गर्म पानी वाले पवित्र ब्रह्म कुंड का निर्माण करते हैं। राजगीर के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली स्वरूप में पुनर्जीवित करने के अलावा नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का समर्थन करेगी।

बजट पर बयान

सर्वसमावेशक बजट

-गोपाल शर्मा
विधायक, सिविल लाइंस

आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प को बल देने वाला वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट देश में विकास की नई परिभाषा गढ़ेगा, यह पूर्ण विश्वास है। इस सर्वसमावेशक बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार।

कर्मचारियों में खुशी

-रमेश सैनी
नर्सेज कर्मचारी नेता

केन्द्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। कर्मचारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया है, जिससे अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिलेगी। इसमें 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5, 7 से 10 लाख रुपए तक 10, 10 से 12 लाख रुपए तक 15, 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी होने पर कर्मचारियों और आमजन के लिए अच्छा कदम है।

आमजन के लिए खास

-हिमांशु जैन
ड्राई फ्रूट्स और खाद्य मसाला व्यवसायी

बजट आमजन के लिए खास है। कृषि के क्षेत्र में अच्छा बजट देने से कृषि उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। जिससे आमजन की रसोई पर सीधा असर पड़ेगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में बढ़ोतरी से मसालों, ड्राई फ्रूट्स, दलहन के उत्पादन,भंडारण और मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा। जिससे रसोई के बजट में भी राहत मिलने की उम्मीद रहेगी।

सोना-चांदी पर घटी कस्टम ड्यूटी, अब 6% ही देनी होगी

सजना के लिए सजने की सौगात, गहने होंगे सस्ते

बेधड़क। नई दिल्ली

वित्त मंत्री ने महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 फीसदी कर दी है। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे। यह आभूषण के शौकीनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।

कीमती धातुओं के संबंध में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोने पर कस्टम ड्यूटी 6% कम करने की घोषणा के बाद मंगलवार को सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। ऐसे में यह सस्ते रेट पर सोना खरीदने का शानदार मौका है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर मंगलवार को सोने के रेट में 4000 रुपए तक की गिरावट आई है। वहीं, चांदी की कीमतें भी 4,800 तक की कमी आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मंगलवार को सोने के रेट में जबरदस्त गिरावट देखी गई। मंगलवार को एमसीएक्स पर सोना 72838 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। इसके बाद दोपहर को 2 बजे के करीब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 5 अगस्त की डिलिवरी वाला सोना 5.46% या 3,967 रुपए की गिरावट के साथ 68,751 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है।

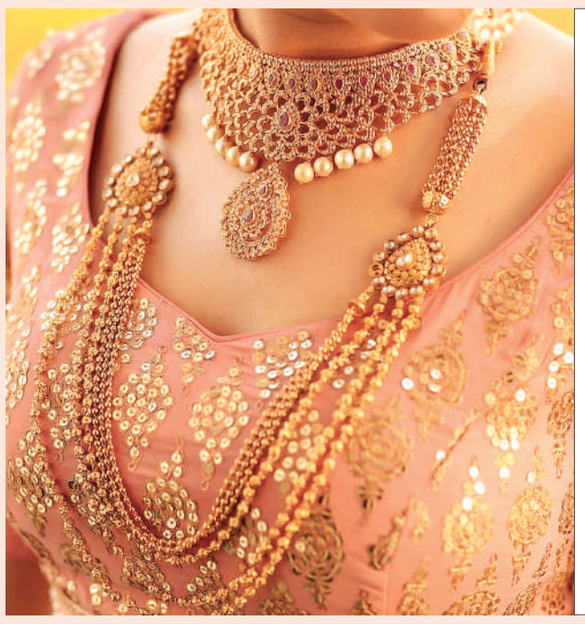

महिला कौशल बढ़ाने के लिए दिए 3 लाख करोड़ रुपए

महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योगों के साथ मिलकर महिला हॉस्टल और बालगृहों की स्थापना करेंगे। यह योजना महिला कौशल कार्यक्रम को प्रोत्साहित करेगी।

2029 तक मिलता रहेगा अनाज

पीएम गरीब कल्याण योजना 5 साल बढ़ाई

बेधड़क। नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश करते हुए सरकार की प्राथमिकताएं गिनाईं। उन्होंने कहा, 'हमने पीएम गरीब कल्याण योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया है। इससे 80 करोड़ से अधिक गरीबों को लाभ हो रहा है। गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना साल 2029 तक जारी रहेगी। योजना में पात्र गृहस्थी राशन कार्ड के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त देने की व्यवस्था है। चूंकि, यह योजना केंद्र सरकार की है इसलिए किसी भी राज्य के लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए देशभर में सरकारी राशन की दुकानें संचालित की जाती हैं। इन दुकानों पर अलग-अलग राशन कार्ड के तहत अलग-अलग मात्रा में राशन दिया जाता है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले करीब 80 करोड़ गरीबों को बिना किसी लागत के प्रति व्यक्ति पांच किलो खाद्यान्न (चावल और गेंहू) अतिरिक्त दिया जाता है।

मनरेगा में परिवार के एक सदस्य को मिलेगा 100 दिन का रोजगार: उन्होंने आगे कहा कि पहले मौजूद मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी) योजना में प्रत्येक उस परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक काम चाहते हैं।

3 अहम दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जीरो

केंद्रीय बजट में कैंसर के रोगियों को मिली बड़ी राहत, सस्ता हो सकेगा इलाज

बेधड़क। नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2024 का पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करते हुए कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि तीन अतिरिक्त कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को माफ किया जाएगा। यह कदम कैंसर मरीजों की वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कैंसर रोगियों को बड़ी राहत देते हुए जिन तीन और दवाओं को सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया गया है उनके नाम ट्रास्टुजुमैब डेरुक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और दुरवालुमैब हैं। ट्रास्टुजुमैब डेरुक्सटेकन एक एंटीबॉडी-ड्रग कॉन्जुगेट है जो विशेष रूप से HER2-पॉजिटिव मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। यह HER2 पॉजिटिव कैंसर कोशिकाओं को टारगेट करती है और उनमें दवा पहुंचाकर उन्हें नष्ट करता है। केंद्रीय मंत्री ने इसके अलावा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के तहत चिकित्सा एक्स-रे मशीनों में इस्तेमाल होने वाले एक्स-रे ट्यूबों और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में किए गए परिवर्तनों के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। ये उपाय केंद्र सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। इसका उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को सपोर्ट देते हुए स्वास्थ्य सेवा की सामर्थ्य और पहुंच को बढ़ाना है।

सेहत को जरूरत से 73% कम बजट दे रही सरकार

2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में 2024-25 तक हेल्थ सेक्टर पर GDP का 2.5% खर्च करने का टारगेट था। इसमें केंद्र और राज्य सरकार, दोनों के खर्च शामिल थे। इस टारगेट को पूरा करने के लिए इस साल हेल्थ सेक्टर पर कुल 8.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाना चाहिए था। इसमें राज्य सरकार को 60% और बाकी 40% केंद्र सरकार को खर्च करना था। इस हिसाब से केंद्र का हेल्थ बजट हर साल 3.3 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए था, जबकि इस बजट में 91 हजार करोड़ करोड़ रुपए दिए गए। यह जरूरत का सिर्फ 27% है।

हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फंड कमी का दिखेगा असर

देश में हेल्थ सर्विस को सही ढंग से चलाने के लिए जितने पैसों की जरूरत है, बजट में उसका 27% ही मिल पाया है। यह जितनी जरूरत है उससे 73% कम है। देश में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर का हाल भी इसी आंकड़े जैसा है। देश के अस्पतालों में जितने बेड की जरूरत है, उसके मुकाबले 37% बेड ही उपलब्ध हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1 लाख आबादी पर कम-से-कम 100 डॉक्टर उपलब्ध होने चाहिए। भारत में 1 लाख आबादी पर 70 से 75 डॉक्टर ही उपलब्ध हैं। अमेरिका में इतनी ही आबादी पर 255 डॉक्टर हैं। अगर आयुर्वेद, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सक को शामिल भी कर लें तो भारत में डॉक्टरों का आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक को पार कर सकता है।

सौ शहरां री सूरत बदळै करियो घणा प्रयास
छोड़ो कसर ना काम म्है, हर घर हुवै उजास

बजट 2024-25 में बुनियादी ढांचे पर फोकस... पीएमजीएसवाई का चरण IV किया जाएगा शुरू

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹11,11,111 करोड़ का 'शगुन'

बेधड़क। नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विगत वर्षों में अवसंरचना का निर्माण करने तथा इसे बेहतर बनाने के लिए किए गए पर्याप्त निवेश का अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

हम अन्य प्राथमिकताओं और राजकोषीय समेकन की आवश्यकताओं के अनुरूप, अगले 5 वर्षों में अवसंरचना के लिए सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाए रखने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह हमारी जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा। इसी तरह बुनियादी ढांचे के लिए मदद प्रदान करने को लेकर राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा कि हम राज्यों को उनकी विकास प्राथमिकताओं के अध्यधीन, अवसंरचना के लिए उसी पैमाने की सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ के दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण का प्रावधान किया गया है। अवसंरचना में निजी निवेश को बढ़ावा देने के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि समर्थकारी नीतियों और विनियमनों के माध्यम से अवसंरचना में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए एक बाजार आधारित वित्तपोषण फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पीएमजीएसवाई के लिए पात्र बने 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए पीएमजीएसवाई का चरण IV आरंभ किया जाएगा।

बजट 2024: पानी सप्लाई और कचरा मैनेजमेंट पर फोकस

देशभर के 100 शहरों की बदलेगी सूरत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश भर के 100 शहरों की तस्वीर बदलने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन शहरों में जलापूर्ति, जलशोधन और कचरे के प्रबंधन के लिए परियोजनाएं लाई जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं में सिंचाई के लिए शोधित जल के इस्तेमाल का भी विचार है। इस तरह अब सिंचाई के लिए जल की कमी दूर होगी। इसके अलावा प्रदूषित जल के निपटान का भी मसला कुछ हद तक हल हो सकेगा। उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकारों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ साझेदारी में बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, जलमल शोधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा देंगे। वित्त मंत्री ने यह ऐलान भी किया है कि देश के 100 शहरों में इन्वेस्टमेंट रेडी औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। सरकार ने बजट में पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय योजना लॉन्च की है। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार होगा और गया में उसका केंद्र होगा। आंध्र प्रदेश में भी औद्योगिक विकास पर जोर दिया जाएगा। इसके तहत विशाखापत्तनम-चेन्नै इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। वहीं हैदराबाद से बेंगलुरु के लिए भी कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इस तरह सरकार ने शहरी विकास के साथ ही औद्योगिक योजना पर भी फोकस किया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास पर भी सरकार ने बड़े खर्च का ऐलान करते हुए ढाई लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।

3 करोड़ आवासों का निर्माण

वित्त मंत्री ने संसद में 'केंद्रीय बजट 2024-25' पेश करते हुए कहा कि देश की जनता ने भारत को सतत विकास के मार्ग पर ले जाने और चहुंमुखी समृद्धि के लिए हमारी सरकार को एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तीन करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण की घोषणा की है, जिसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध बजट में किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की घर संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। इसमें किफायती दरों पर ऋण सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान है। किराये पर मिलने वाले आवासों के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि औद्योगिक कामगारों के लिए निजी सहभागिता योजना (वीजीएफ) सहायता और निजी कंपनियों के साथ साझेदारी (पीपीपी) मोड में डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा प्रदान की जाएगी। किराए के आवास बाजारों के लिए समर्थकारी नीतियां तथा विनियम भी बनाए जाएंगे।

बजट में ये खास

तीन नए एक्सप्रेस-वे: बिहार के पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे, बोध गया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा एक्सप्रेस-वे और बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल बनाया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स के लिए 26 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत गया में औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा।

25 हजार गांवों में सड़कें: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे फेज में 25 हजार गांवों तक सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं साथ ही नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे।

दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर: आंध्रप्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत राज्य को 15,000 करोड़ रुपए की विशेष पैकेज दिया गया है। यह पैसा विशाखापट्टनम -चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद-बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए खर्च किया जाएगा।

दो मंदिरों में कॉरिडोर: काशी की तर्ज पर बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा।

बजट पर- बयान

गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट

गजेंद्र सिंह शेखावत
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय बजट 2024-25 को समाज के हर वर्ग को शक्ति प्रदान करने वाला और गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बताया है। शेखावत ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये जो नए मध्य वर्ग बना है, ये बजट उनके सशक्तीकरण की निरंतरता का बजट है।

विकसित भारत के लक्ष्य का रोडमैप है बजट

दिया कुमारी
उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री

उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय बजट को किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट बताते हुए कहा है कि इसमें विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का रोड मैप है। यह देश के सभी वर्गों की आशाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। महिला और बालिकाओं के लिए केंद्रीय बजट में तीन लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की भी घोषणा की गई है, इसके तहत 25 हजार गांवों तक सड़क बनाई जाएगी। गया के विष्णुपाद मंदिर और बौधगया के महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित करने की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये दोनों कॉरिडोर, देश-विदेश से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करेंगे।

बजट से राजस्थान को हाथ लगी निराशा

अशोक गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा है कि इससे राजस्थान को केवल निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि राजनीतिक कारणों से केंद्र सरकार ने केवल आंध्र प्रदेश एवं बिहार को ही पूरे देश का बजट सौंप दिया हो। भौगोलिक एवं सामाजिक रूप से हमारे राजस्थान को विशेष पैकेज की आवश्यकता थी परंतु पूरे बजट भाषण में राजस्थान का नाम तक नहीं आया, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान तथाकथित डबल इंजन की सरकार से डबल विकास के भ्रामक दावे के बगैर पीएम का कोई भाषण समाप्त नहीं होता था। गहलोत ने कहा केंद्र सरकार ने ईआरसीपी पर भी कोई घोषणा न कर राजस्थान के हितों के साथ खिलवाड़ किया।

हर महीने मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली

एक करोड़ घरों में लगेंगे सोलर पैनल

बेधड़क। नई दिल्ली

बजट में केंद्र सरकार ने 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का ऐलान किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिनसे बिजली का उत्पादन होगा। इस योजना से 1 करोड़ घरों को फायदा मिलेगा। उन्हें हर महीने 300 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगी। बजट 2024 भाषण के दौरान उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 1.28 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 14 लाख एप्लिकेशन मिल चुके हैं। इस योजना के प्रति लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। लिहाजा इस योजना को बढ़ावा दिया जाएगा।

- विद्युत भंडारण और समग्र उर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए पम्पड स्टोरेज परियोजाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति लाई जाएगी।
- परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों और स्मॉल और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर का अनुसंधान और विकास।
- उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर (एयूएससी) प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से एनटीपीसी और बीएचईएल का एक संयुक्त उद्यम 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करेगा।
- हार्ट टू एबेट उद्योगों के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा।
- 60 कलस्टरों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा से स्वच्छ उर्जा में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

पहले शेयर बाजार हुआ धड़ाम... बाद में संभला

बेधड़क. मुंबई। शेयर मार्केट में बजट डे पर भारी उतार चढ़ाव रहा और कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने के बाद बाजार में तगड़ी गिरावट हुई। हालांकि ट्रेडिंग सेशन के अंत में मार्केट में अधिक गिरावट नहीं रही और निफ्टी केवल 30 अंकों की गिरावट और सेंसेक्स 73 अंकों की गिरावट के बाद क्लोज

कैपिटल गेन टैक्स कितना बढ़ा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में साफ किया है कि लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स को अब 10% से 12.5% कर दिया गया है। वहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से 20% बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, कैपिटल गेन के लिए छूट की सीमा को 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की जाएगी।

निवेशकों को लगा झटका

पहले से माना जा रहा था सरकार कैपिटल गेन टैक्स को लेकर ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेशकों को झटका दिया है। कैपिटल गेन टैक्स के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बढ़ाकर 12.5% किया गया। इसी के साथ शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है।

ऐलान के बाद शेयर बाजार हुआ बेहाल

कैपिटल गेन टैक्स संबंधी ऐलान के बाद दोपहर 12 बजकर 51 मिनट पर बीएसई का सेंसेक्स 631.61 अंक या 0.78 % गिरने के बाद 79,870.47 स्तर पर आ गया है। वहीं, एनएसई का निफ्टी 151.95 अंक या 0.62% की गिरावट के बाद 24,357.30 स्तर पर आया।

प्रदेश के जवाहरात उद्योग, सोलर एनर्जी को लगेंगे पंख

जयपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया। इसमें गरीब, महिला, युवा और किसानों पर फोकस रखा गया। वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं की हैं, उनका राजस्थान के जवाहरात उद्योग, पर्यटन उद्योग, सोलर एनर्जी इंडस्ट्री और खनिज उद्योग को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग के लिए टैक्स में छूट की घोषणा की है। इससे जयपुर के जवाहरात उद्योग को सीधा फायदा होने की उम्मीद है। पर्यटन के क्षेत्र में देश को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की उन्होंने बात की है, जिससे राजस्थान के पर्यटन उद्योग को पंख लगने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही सोलर इंडस्ट्री और मिनरल इंडस्ट्री को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं, उससे भी प्रदेश में सोलर इंडस्ट्री और खनिज उद्योग को भी फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान सोलर एनर्जी का हब है और देश मे सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी उत्पादन वाला राज्य है। खनिज के लिहाज से भी राजस्थान समृद्ध माना जाता है।

बजट के लिए पीएम और वित्त मंत्री का आभार

राजस्थान में विकास के नए आयाम होंगे स्थापित: जोशी

बेधड़क। जयपुर

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत पूर्ण बजट को विकसित भारत के ध्येय को बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बजट बताया, जिसमें किसान, युवा, गरीब, महिला सहित समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र को समाहित किया गया है।

बजट में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्था बने इसकी झलक साफ दिखाई देती है। उन्होंने दमदार और शानदार बजट के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में विकसित भारत की आधारशीला रखी गई थी। बजट में जैविक खेती को बढ़ावा और किसानों को अधिक सुविधा मिले, एमएसएमई सेक्टर से लेकर कौशल विकास तक पांच साल में चार करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजागार देने, तीन करोड़ महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनेक योजनाओं का प्रावधान बजट में किया है। इसके अलावा सड़क, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, शिक्षा, पीएम सूर्य घर योजना, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, सहित हर क्षेत्र पर फोकस किया गया है।

देश-प्रदेश की प्रगति के लिए हितकारी रहेगा बजट

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा यह बजट देश और प्रदेश की प्रगति के लिए हितकारी रहेगा। राजस्थान में जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की घोषणा, दलहन और तिलहन के लिए नए मिशन की घोषणा व इनके उत्पादन, भंडारण व मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास करने से प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा। बजट से प्रदेश में जैविक कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटने से जयपुर के जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार को काफी लाभ होगा। इस बार केंद्र से राजस्थान को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में सात हजार करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे। इसके लावा अन्य योजनाओं से भी राजस्थान को करोड़ों रुपए मिलेंगे। ऐसी ही अनेक घोषणाओं से प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पिछले दस सालों में देश की जनता ने विकास देखा। कांग्रेस ने तो सिर्फ वादे और नारे ही दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा।

पढ़ो लिखो हुनर बढ़े इंटरनशिप रो मेल
रिपियां को टोटो नहीं, रुजगार रो खेल

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में युवाओं के लिए की आकर्षक घोषणाएं

मोदी सरकार 3.0 @ युवाओं की बल्ले-बल्ले

बेधड़क | नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2024 को पेश किया। निर्मला सीतारमण ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखा है। शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने, प्रतिभाओं को पोषित करने और उद्योग-विशिष्ट कौशल और प्रशिक्षण देकर रोजगार को बढ़ावा देने पर सरकार के फोकस को रेखांकित करता है। इस वर्ष का बजट युवाओं को कौशल देने और उनके लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। इस बजट की नौ प्राथमिकताओं में से एक नौकरी है। इसलिए यह बढ़ा हुआ बजटीय आवंटन छात्रों को उनके मनचाहे करियर को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।

रोजगार, कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ का किया प्रावधान

केंद्रीय बजट में 4.1 करोड़ युवाओं के रोजगार, कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतरमण ने कहा, युवा कल्याण के लिए 1.48 लाख करोड़ पहले ही दिया जा चुका हैं। इस बजट में 9 प्राथमिकताएं हैं। कृषि विकास, रोजगार और कौशल, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्सट जनरेशन रिफॉर्म सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मिडिल क्लास और रोजगार पर फोकस है।

रोजगार संबंधी तीन योजनाएं शुरू होंगी

वित्त मंत्री ने कहा कि वह रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेंगी। ये योजनाएं ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी। पहली योजना के तहत सभी क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वालों को एक महीने का वेतन प्रदान किया जाएगा। दूसरी योजना में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेगी।

20 लाख महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ईपीएफओ के जरिए नई इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई हैं। डीबीटी से 210 लाख युवाओं को फायदा होगा। महिला कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सरकार नई योजना शुरू कर रही है। इस योजना में 20 लाख महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। कई नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक के एजुकेशन लोन का प्रावधान किया जा रहा है।

ई-कॉमर्स और एक्सपोर्ट हब से रोजगार के मौके

वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में रोजगार के मौके तैयार किए जाएंगे। 50 मल्टी फूड प्रोडक्ट के लिए सहायता दी जाएगी। पीपीपी मॉडल से ई-कॉमर्स और एक्सपोर्ट हब भी बनाए जाएंगे।

- सर्विस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री के 5 ऐलान
- प्राइवेट सेक्टर को हर क्षेत्र में सरकार की स्कीम्स से मदद दी जाएगी।
- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए।
- विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
- रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
- शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी।
- 1 हजार ITI को डेवलप किया जाएगा। बच्चों के लिए क्रेच खोले जाएंगे। ई-श्रम पोर्टल को अन्य सरकारी पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा ताकि नौकरी खोजने वालों को कंपनियों और स्किल ट्रेनिंग संस्थानों से मिलाया जा सके।

NPS वात्सल्य योजना करेंगे बच्चों का भविष्य सुरक्षित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट में सरकार की नई पेंशन योजना (NPS) 'वात्सल्य' का एलान किया है। योजना के मुताबिक अब माता-पिता और अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर इस योजना में निवेश कर सकेंगे। नाबालिग बच्चों के वयस्क होने पर उनके खाते को सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस योजना से युवाओं का वित्तीय भविष्य सुरक्षित होगा।

शिक्षा के लिए ₹10 लाख का लोन, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2024 की 9 प्राथमिकताओं में प्रोडक्टिविटी, रोजगार, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और सुधार शामिल हैं। सरकार नौकरी की तलाश कर रहे 30 लाख युवाओं को एक महीने का PF कंट्रीब्यूशन देकर प्रोत्साहन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाएगी। एक हजार ITI को हब एंड स्पोक मॉडल में अपग्रेड किया जाएगा। सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बजट में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके साथ ही घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल एक लाख छात्रों को दिये जाएंगे, जिससे ऋण राशि 3% की वार्षिक ब्याज छूट के साथ दी जाएगी। सरकार संवर्धित कोष की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इससे हर साल 25 हजार विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। इसके साथ ही उद्योगों से सहयोग से कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।

कामकाजी छात्रावास किए जाएंगे स्थापित

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें इंटर्नशिप भत्ते के रूप में 5000 रुपए प्रति माह और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता भी देगी। कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। छात्रावासों और क्रेच के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी सरकार समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी।

किसानों से लेकर श्रमिकों तक को ऑनलाईन पॉर्टल किया जाएगा

भारत सरकार ने बजट 2024 पेश कर दिया है और इसमें ढेरों सुधार व बदलाव देखने को मिले हैं। एक बार फिर सरकार ने कई काम डिजिटल करने का फैसला किया है और किसान से लेकर श्रमिकों तक को ऑनलाइन पोर्टल्स से कनेक्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई मुद्दों पर बात की और डिजिटल इंडिया पर भी जोर दिया। सरकार ने विकसित भारत बनाने के रोडमैप का जिक्र तो किया ही है, इसके अलावा किसानों से लेकर रोजगार और शहरी विकास तक पर बात की गई। वित्तमंत्री ने बताया कि किस तरह नए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से किसानों से लेकर श्रमिकों तक को फायदा मिलेगा।

इनका कहना है :

समग्र, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी तथा मध्यम वर्ग सहित सभी वर्गों को लाभान्वित करने वाला बजट।
धर्मेन्द्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा मंत्री

'सबको अवसर' के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में रोज़गार सृजन और युवा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश के सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित किया गया है। 'हर किसी के लिये हर संभव प्रयास' यह मंत्र इस बजट के मूल केंद्र में दिखाई पड़ता है।
मनसुख मांडविया
केंद्रीय युवा मामले मंत्री

20 लाख युवाओं को दिया जाएगा कौशल विकास प्रशिक्षण

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत चौथी योजना के रूप में राज्य सरकारों और उद्योग जगत के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना की घोषणा की जा रही है। इस योजना के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक तरीके से विकसित किया जाएगा।

500 शीर्ष कंपनियों में युवाओं को पेड इंटर्नशिप का मिलेगा मौका

500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण करने के लिए योजना की शुरूआत होगी। उन्हें रोजगार के अवसरों के लिए 12 महीनों का अनुभव मिलेगा। इस योजना के तहत 5,000 रुपये प्रतिमाह का प्रशिक्षण भत्ता और 6,000 रुपये की एकबारगी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए कंपनियों से प्रशिक्षण और इंटर्नशिप लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा अपनी सीएसआर निधियों से वहन की जाएगा। ऐसे युवा जो 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के हैं और बेरोजगार हैं, किसी भी शैक्षिक गतिविधि दूर है वे इसका लाभ लेंगे।

यह है योजना

एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत अभी नहीं हुई है। बजट में सिर्फ एलान किया गया है। सरकार का कहना है कि जल्द ही योजना को शुरू किया जाएगा। यह योजना नाबालिगों की खातिर होगी। इसमें माता-पिता और अभिभावक बच्चे के नाम पर एनपीएस खाते में निवेश करने के योग्य होंगे। बच्चे के 18 साल पूरे होने पर उसका खाता एक सामान्य एनपीएस खाते में बदल जाएगा। भविष्य में आपके बच्चों को एकमुश्त राशि और पेंशन का लाभ मिलेगा।

क्या है एनपीएस?

एनपीएस एक टैक्स सेविंग स्कीम है। इस योजना के मुताबिक 18 से 60 साल के बीच कोई भी व्यक्ति अपना एनपीएस खाता देश के किसी भी बैंक में खोल सकता है। 60 साल की उम्र के बाद निवेशक को धनराशि का एक हिस्सा मिलता है। जबकि दूसरा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है। अभी तक कोई भी नाबालिग इस योजना में निवेश नहीं कर सकता था। मगर अब वात्सल्य के तहत नाबालिग के नाम पर भी माता-पिता निवेश कर सकेंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) एनपीएस को रेगुलेट करती है।

प्रधानमंत्री पैकेज योजना के तहत होगा क्रियान्वयन

5 वर्ष में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसरों का मौका

बेधड़क | जयपुर

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 'केंद्रीय बजट 2024-25' पेश करते हुए कहा कि इस बजट में हमने मुख्य रूप से रोजगार, कौशल विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा मध्यम वर्ग पर ध्यान केन्द्रित किया है। नई सरकार के गठन के बाद पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने पांच योजनाओं और नई पहल के एक पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज का उद्देश्य 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार सृजन, कौशल विकास और अन्य अवसर उपलब्ध कराना है, इसके लिए पांच वर्ष की अवधि में दो लाख करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता राशि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए एक लाख 48 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के लिए तीन योजनाओं को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि- ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार रोजगार पाने वाले को पहचान दिलाने में मदद करेंगी। साथ ही रोजगार देने वाले तथा रोजगार प्राप्त करने वाले का सहयोग करेंगी। ये योजनाए तीन केटेगरी में लागू हो सकेंगी।

पहली बार रोजगार पर 15 हजार रुपए

यह योजना सभी प्रमुख औपचारिक कार्य क्षेत्रों में कामगार के रूप में शामिल होने वाले नये युवाओं को एक महीने का वेतन उपलब्ध कराएगी। इससे दो वर्ष तक 2.1 करोड़ युवा लाभांवित होंगे। इस योजना में शामिल होने के लिए पात्रता की सीमा वेतन के रूप में एक लाख रुपये प्रतिमाह तक होगी। कर्मचारी भविष्य निधि- ईपीएफओ में पंजीकृत हुए पहली बार रोजगार पाने वाले लोगों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से एक महीने का वेतन 15 हजार की तीन किस्तों में दिया जाएगा और यह अधिकतम होगा। इस योजना से 210 लाख युवाओं के लाभान्वित होने की आशा है।

विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन

इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो पहली बार रोजगार पाने वाले कामगारों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। योजना के अंतर्गत पहली बार रोजगार पाने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं के लाभान्वित होने की आशा है। मुख्य रूप से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सीधे तौर पर एक विनिर्दिष्ट पैमाने पर रोजगार के पहले चार वर्षों में ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यदि पहली बार रोजगार पाने वाले कामगार की सेवाएं उसकी नियुक्ति के 12 महीनों के अंदर समाप्त कर दी जाती है तो सब्सिडी नियोक्ता के द्वारा लौटाई जाएगी।

नियोक्ताओं को सहायता मुहैया करवाएंगे

रोजगार देने वाले नियोक्ताओं पर केंद्रित इस योजना में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को शामिल किया जाएगा। इसमें एक लाख रुपए प्रतिमाह के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगारों की गणना की जाएगी। सरकार, प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ताओं को ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक 3,000 रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना से 50 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

युवाओं एवं मध्यम वर्ग को ताकत देने वाला बजट

डॉ. अमित वर्मा
स्वतंत्र टिप्पणीकार

किसी भी देश की सरकार द्वारा प्रस्तुत एक वित्तीय योजना जिसें हम केन्द्रीय बजट के नाम से जानतें है, जिसमें आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है। इस केन्द्रीय बजट में सरकार के विभिन्न खर्चों और आय के स्रोतों का विस्तृत विवरण शामिल होता है। केन्द्रीय बजट का देश की अर्थव्यवस्था और नागरिकों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर चुकी हैं। सरकार ने वेतन भोगियों, पेंशन भोगियों, किसान, महिलाओं, युवा, छात्रों समेत कई वर्गों के लिए बड़े ऐलान किए। अगर आसान भाषा में कहें तो मध्यम वर्गीय परिवार एंव छात्रों के फायदे का बजट है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम पैकेज के तहत रोजगार से जुड़ी स्किल स्कीम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह योजना ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी। इसमें पहली बार काम करने वालों को सभी औपचारिक क्षेत्रों में काम शुरू करने पर एक महीने का वेतन मिलेगा। एक महीने का वेतन डीबीटी के जरिये तीन किस्तों में 15,000 रुपये तक दिया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन होगी और इससे लाखों युवाओं को लाभ होने की उम्मीद है।

> गोल्ड निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म की समय सीमा पहले 36 महीने की होती थी। लेकिन अब इसे घटाकर 24 महीने कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अब 20 प्रतिशत की जगह 12.5 प्रतिशत लगेगा। इन फैसलों का असर आज सोने, चांदी के कीमतों पर देखने को मिला है। गोल्ड और सिल्वर के भावों में भी कमी आई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले बजट की तुलना 32 प्रतिशत ज्यादा है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नौकरियों और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित पांच योजनाओं का एलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार पहली बार रोजगार के तहत एक लाख रुपये से कम वेतन होने पर कर्मचारी भवष्यि निधि संगठन (ईपीएफओ) में पहली बार पंजीकरण करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद देगी, जो तीन कश्तिों में मिलेगी। ये किश्तें सीधे बैंक में स्थानांतरण (डीबीआई) के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना से 210 लाख युवओं को मदद दी जाएगी।

वित्त मंत्री ने उत्पादन क्षेत्र में रोजगार सृजन को पहली बार कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ी योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना रोजगार के पहले चार वर्षों के दौरान कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ईपीएफओ योगदान के संबंध में प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे प्रत्यक्ष तौर पर 30 लाख युवाओं को लाभ होगा और यह सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगा। इसके अलावा सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक प्रति माह 3,000 रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति नियोक्ताओं को करेगी। इस पहल का उद्देश्य 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करना है। वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इस मद में बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सीतारमण ने कहा कि सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर प्रदान करेगी, जिसमें ऋण राशि का 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा।

सरकार ने इनकम टैक्स के न्यू रिजीम में भी रेट में मामूली बदलाव किए हैं। खास बात है कि यह उनकी तरफ से पेश किया जाने वाला 7वां बजट था। इससे पहले चुनावी साल होने के चलते 1 फरवरी 2024 को पेश हुए अंतरिम बजट में खास नीतिगत बदलाव नहीं देखे गए थे। साथ ही मध्यमवर्गीय के लिए खास घोषणाएं सरकार के अंतरिम बजट में शामिल नहीं थीं। हालांकि, अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पूर्ण बजट में सरकार टैक्स पेयर्स और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। खास बात है कि बीती दो सरकारों से परे इस बार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में जनता दल यूनाइटेड और तेलुगू देशम पार्टी की भी भागीदारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने में असफल रही थी।

बजट ऐलान के बाद बाहर से आयातित किया गया मोबाइल फोन, चार्जर /एडाप्टर की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। कुछ कैंसर की दवाओं के दाम भी घटने की उम्मीद है। सरकार ने ताम्बाकू पर टैक्स नहीं बढ़ाया है जिस वजह से सिगरेट आदि के दाम में इजाफा नहीं देखने को मिलेगा। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बजट में इस बार बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने विदेशी कंपनियों पर लगने वाले कॉरपोरेट टैक्स रेट्स को घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया है। बजट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में विदेशी कंपनियों की इनकम पर लगने वाला टैक्स 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत किया गया है। इकनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि अमेरिका और यूरोप के कई देश चीन से अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हटाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में भारत उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। बजट ऐलान को एक्सपर्ट इसी से जोड़कर देख रहे हैं।

सरकार ने बजट के जरिए गोल्ड की खरीदारी करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। बजट में बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, एग्री सेस को 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया है। सरकार ने एक और बड़ा चेंज किया है। अब गोल्ड इंवेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म की समय सीमा 36 महीने की जगह 24 महीने होगी। वहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए दो लाख करोड़ का बजट

नींव को मजबूत करने वाला बजट

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ साहित्यकार
व पत्रकार

इस आम बजट की तीन खास बातें हैं, जो रोजगार से लेकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली साबित हो सकती हैं। एक कृषि, दो रोजगार और तीन आयकर दाताओं को राहत। इसीलिए इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानते हुए कहा है कि 'यह आम बजट पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2029 तक विकसित भारत की आधारशिला रखने में अहम भूमिका निभाता रहेगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने खेती में उत्पादकता, बेरोजगारों को नामी कंपनियों में प्रशिक्षण देते हुए पांच हजार रुपए की परिश्रमिक राशि की आर्थिक सहायता और बाजार को बढ़ावा देने की दृष्टि से कर सारणी में करप्रदाताओं को राहत। इसके अलावा समग्र मानव संसाधन विकास, ऊर्जा सुरक्षा, ढांचागत विकास, शोध-अनुसंधान जैसे विषयों को प्राथमिकता देते हुए बजट प्रावधान किया गया है।

> किसान एमएसपी के लिए अर्से से कानूनी रूप देने की मांग कर रहे हैं। यदि इसे कानूनी रूप दे दिया जाता है तो करीब 17 लाख करोड़ रुपए वार्षिक अतिरिक्त खर्च आएगा, नतीजतन देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। किसान उन्हीं फसलों को उगाएंगे, जिन पर ज्यादा सब्सिडी मिलेगी और जिनकी बाजार में मांग ज्यादा होगी।

> तीन से सात लाख रुपए की आय पर पांच फीसदी, सात से दस लाख पर 10 फीसदी, दस से बारह लाख पर 15 फीसदी, बारह से पन्द्रह लाख पर 20 फीसदी और पन्द्रह लाख से अधिक आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। जो कि करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है। इससे बाजार में पैसे की तरलता बढ़ेगी और व्यापारियों को आर्थिक लाभ होगा। बजट में कैंसर की दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चॉर्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सौर ऊर्जा संयंत्र, चमड़ा और समुद्री खाद्य साम्रगी सस्ते होंगे। सौर घर योजना पर सब्सिडी जारी रहेगी।

युवाओं को रोजगार देश में इस समय एक बड़ी समस्या के रूप में देखी जा रही है। उच्च एवं तकनीकि शिक्षा में दक्ष होने के बावजूद रोजगार दूर की कौड़ी बना हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पहल करते हुए रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया है। पांच वर्षों में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं के लिए दक्षता प्राप्त करने हेतु 500 स्थापित कंपनियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन युवकों को केंद्र सरकार पांच हजार रुपए प्रतिमाह सीधे खाते में जमा कराएगी। इस बजट में किसान और कृषि की स्थिति को मजबूत बनाने के नजरिए से 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। पिछले वर्श इस मद में 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। अतएव अब 25000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं। पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। हालांकि किसानों को फसल पर दी जाने वाली सब्सिडी पर इस बजट में कोई नया प्रावधान नहीं है। किसान एमएसपी के लिए अर्से से कानूनी रूप देने की मांग कर रहे हैं। यदि इसे कानूनी रूप दे दिया जाता है तो करीब 17 लाख करोड़ रुपए वार्षिक अतिरिक्त खर्च आएगा, नतीजतन देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। किसान उन्हीं फसलों को उगाएंगे, जिन पर ज्यादा सब्सिडी मिलेगी और जिनकी बाजार में मांग ज्यादा होगी। ऐसे में मोटे अनाज, जिनमें पोषक तत्व अधिक होते हैं, उन्हे किसान खेतों में नहीं बोएंगे। जबकि बीमार होते देश के लिए मोटे अनाज आज की जरूरत बन गई है।

इस बजट में आम करदाता को खुश रखने की कोशिश की गई है, इसलिए कर सारणी में सुधार किया गया है। अब तीन लाख की आमदनी पर कोई कर नहीं लगेगा। तीन से सात लाख रुपए की आय पर पांच फीसदी, सात से दस लाख पर 10 फीसदी, दस से बारह लाख पर 15 फीसदी, बारह से पन्द्रह लाख पर 20 फीसदी और पन्द्रह लाख से अधिक आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। जो कि करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है। इससे बाजार में पैसे की तरलता बढ़ेगी और व्यापारियों को आर्थिक लाभ होगा।

बजट में कैंसर की दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चॉर्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सौर ऊर्जा संयंत्र, चमड़ा और समुद्री खाद्य साम्रगी सस्ते होंगे। सौर घर योजना पर सब्सिडी जारी रहेगी। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है। सोना और चांदी के गहनों पर भी यह ड्यूटी घटाकर 6 प्रतिशत कर दी गई है। संचार, उपकरण 15 प्रतिशत और प्लास्टिक का समान 25 प्रतिशत महंगे किए गए हैं। यह साम्रगी इसलिए महंगी की गई है, क्योंकि यह साम्रगी खराब होने के बाद फेंक दी जाती है, जिससे हर तरह का प्रदूषण बढ़ता है। साथ ही पशुधन के मुंह में भी यह साम्रगी चली जाती है, जिससे जानवर बेमौत मारे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार नीतिश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैशाखियों पर टिकी है। अतएव इन दोनों नेताओं की मांग पूरी करते हुए बिहार को 59 हजार करोड़ रुपए और आंध्रप्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है। लिहाजा माना जा रहा है कि पूरी पांच साल राजग गठबंधन सरकार केंद्रीय सत्ता में बनी रहेगी।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यंग्य

खोदा पहाड़ और ...निकली चुहिया!

आशीष सकलेचा
व्यंग्यकार

घुमक्कड़ बनवारीलाल रोज सुबह लालाजी की रेस्तरां पर पोहा- कचौड़ी खाने जाता उसके लिए बीस रुपए का इंतजार कैसे भी कर ही लेता था। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था की वह पैसे का जुगाड़ नहीं कर पाता हो। ऊपर वाला भी न जाने क्यों उस पर इतना मेहरबान रहता था। वैसे यह अक्सर देखा गया है कि खाने-पीने वालों के पास दूध लाने के लिए पैसे नहीं रहते हैं,पर अपने खाने-पीने के लिए कहीं से भी, कैसे भी ये पैसों का जुगाड़ कर ही लेते हैं। खैर यह सब बात छोड़ो अपन अब असली मुद्दे अर्थात बनवारीलाल पर आते हैं। गांव में कई रेस्तरां हैं पर बनवारीलाल लालाजी की रेस्तरां पर ही जाता है। आप सोच रहे हैं कि गांव में केवल लालाजी का रेस्तरां ही प्रसिद्ध होगा, इसलिए बनवारीलाल लाला जी के रेस्तरां पर ही जाता है, पर ऐसा नहीं है। चलो मैं आपको असली बात बता ही देता हूं कि बनवारीलाल लालाजी के रेस्तरां पर ही क्यों जाता है।

लालाजी का रेस्तरां बहुत बड़ा है, बहुत लोगों का आना- जाना लगा ही रहता है, चाय - नाश्ता करते ही रहते हैं। चाय- नाश्ते के बहाने वहां लोग किसी न किसी बात पर चर्चा, बहस, गपशप करते ही रहते थे- जैसे राजनीति, बाबाओं, चुनाव, खेल एवं उस समय के तात्कालिक हालातों पर और राहुल-मोदी आदि पर। बनवारीलाल को उनकी चर्चा, बहस सुनने में बहुत मजा आता है। यूं कहें कि उसे परम आनंद मिलता है तो गलत नहीं होगा। हमारे देश की कई विशेषताएं है उनमें से एक प्रमुख विशेषता यह है की यहां मुफ्त के रायचंद बहुत पाए जाते हैं। जिनके घर में परिवार वाले उनकी राय नहीं मानते हैं पर वे सरकार को राय देने से नहीं चूकते। जैसे वे बहुत बड़े अर्थशास्त्री (भले पांचवीं फेल) हों। अब जब सब मुद्दे खत्म हो गए तो नया बजट आने की आहट मात्र से ही रायचंदों की राय देने का सिलसिला शुरू हो गया है कि सरकार को ऐसा बजट बनाना चाहिए, वैसा बजट बनाना चाहिए। बनवारीलाल कम पढ़ा हुआ था, इसलिए बजट की सारी बातें उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी, पर फिर भी वह कान लगाए सुन रहा था। अगले दिन जब केंद्र सरकार की ओर से संसद में वित्तमंत्री द्वारा बजट पेश किया जा रहा था, उसका सीधा प्रसारण टीवी पर आ रहा था तो लालाजी के रेस्तरां में सभी टकटकी लगाए देख रहे व कान खोलकर सुन रहे थे, परंतु बनवारीलाल के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। यह सोचते हुए वह घर की तरफ चल दिया कि टीवी से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कल अखबार में बजट के बारे में आसानी से विस्तार से पढ़ लेगा। अगले दिन बनवारीलाल ने सुबह नाश्ते के लिए बीस रुपए का जुगाड़ करने से पहले अखबार के लिए पांच रुपए का जुगाड़ किया। बस स्टैंड जाकर अखबार बेचने वाले से उसने अखबार खरीदा। बजट के कारण विशेष पृष्ठ होने से अखबार का वजन कुछ ज्यादा था, बनवारीलाल उससे बहुत प्रसन्न था। पूरे अखबार में बजट ही बजट की खबरें देख उसकी आंखे चकाचौंध हो गई। उसने बजट की सभी खबरे पढ़ी व उनको समझने का प्रयास किया, परंतु सीधे - साधे, सरल बनवारीलाल के लिए अर्थशास्त्री भाषा व गणितीय आंकड़े समझ से परे हो गए। बजट की वे खबरे उसके ले लिए " काला अक्षर भैंस बराबर हो गई।" उसने पांच रुपए खर्च कर अखबार खरीदा पर समझ न आने के कारण" खोदा पहाड़ और निकली चुहिया" वाली बात हो गई। वह फिर पोहा- कचौड़ी के लिए बीस रुपए का इंतजाम कर लालाजी के रेस्तरां पर इस उम्मीद से पहुंच गया कि बजट के बारे में लोगों की चर्चा से उसे कुछ समझ में आ जाएगा। वहां कुछ रायचंदों के बीच बजट को लेकर इस तरह से चर्चा चल रही थी, मानो वे किसी समाचार चैनल के स्टूडियो में बैठे हों। कोई बजट के पक्ष में दलीलें दे रहा था तो कोई विपक्ष में तर्क दे रहा था। बेचारा बनवारीलाल अगले बजट के इंतजार में है...।

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री, राजस्थान
@BhajanLalBJP
आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।

अभिनेता मनोज कुमार का 87वां जन्मदिन आज

फिल्मों में भारतीयता की छाप और देशभक्ति का पाठ

जाहिद खान
स्वतंत्र टिप्पणीकार

फिल्मी दुनिया में अदाकार मनोज कुमार को एक ऐसी हरफ़नमौला शख़्सियत के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने अपने बेजोड़ अभिनय के साथ-साथ निर्देशन, लेखन, संपादन और फिल्म निर्माण की प्रतिभा से दर्शकों के दिल में अपनी ख़ास पहचान बनायी है। 'शहीद', 'उपकार', 'शोर', 'यादगार', 'क्रांति', 'पूरब और पश्चिम', 'रोटी-कपड़ा और मकान' जैसी लाजवाब और कभी न भुलाए जाने वाली फिल्में उन्होंने अपने चाहने वालों को दी हैं। उनके द्वारा निर्देशित ज्यादातर फिल्में भारतीयता और देशभक्ति की भावना से ओत-पोत हैं।

इन फिल्मों और उनके गाने सुनकर कई पीढ़ियों ने देशभक्ति का पाठ सीखा है। आजादी की वर्षगांठ हो, गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता सेनानियों की जयंती-पुण्यतिथि के आयोजन मनोज कुमार की फिल्मों के गाने मसलन 'ऐ वतन-ऐ वतन हमको तेरी कसम', 'सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है', 'मेरा रंग दे बसंती चोला', 'अब के बरस तुझे धरती की रानी', 'मेरे देश की धरती सोना उगले', 'भारत का रहने वाला हूं' जरूर बजते हैं। इन गानों के बिना यह आयोजन मानो अधूरे होते हैं। अविभाजित भारत के एबटाबाद में

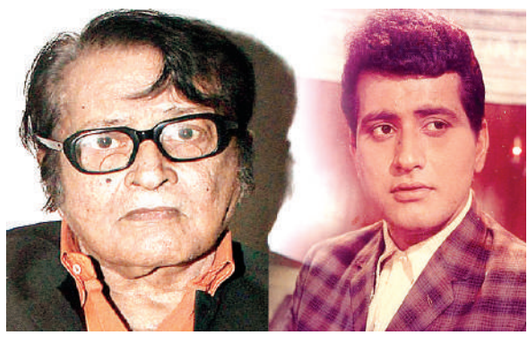

24 जुलाई, 1937 को जन्मे मनोज कुमार का परिवार बंटवारे के बाद, नई दिल्ली में आकर बस गया। यहीं उनकी तालीम हुई। उनका असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी है, फिल्मों में आकर वह मनोज कुमार हो गए। अपने बचपन में वे अभिनय सम्राट दिलीप कुमार से बेहद प्रभावित थे और उन्हीं की तरह हीरो बनना चाहते थे।

अपने इस ख़्वाब को लेकर वे मायानगरी मुंबई पहुंचे। फिल्मों में काम की तलाश में उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। छोटी-छोटी भूमिकाओं से शुरुआत करने के बाद, साल 1961 में निर्देशक एचएस रवैल ने उन्हें अपनी फिल्म 'कांच की गुड़िया' में हीरो का रोल दिया। फिल्म नाकाम रही। इसके बाद उन्हें और भी कई फिल्में मिलीं, लेकिन यह सभी फिल्में टिकिट खिड़की पर नाकामयाब साबित हुईं। साल 1962 में आई निर्देशक विजय भट्ट की 'हरियाली और रास्ता' वह फिल्म थी, जिसमें मनोज कुमार को कामयाबी का पहला स्वाद मिला। एक बार उन्होंने जो कामयाबी का दामन थामा, तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 60 और 70 के दशक में मनोज कुमार ने एक के बाद एक कई सुपर हिट फिल्में लाईन से दीं। 'वो कौन थी', 'गुमनाम', 'हरियाली और रास्ता', 'हिमालय की गोद में', 'दो बदन', 'पत्थर के सनम', 'नील कमल', 'शोर', 'साजन', 'बेईमान', 'दस नंबरी', 'सन्यासी' और 'पहचान' जैसी अनेक फिल्में इस लंबी फ़ेहरिस्त में शामिल हैं।

दिलीप कुमार जिन्हें मनोज कुमार फिल्मी दुनिया में अपना आदर्श मानते थे, आगे चलकर उन्होंने उनके साथ दो फिल्में 'आदमी' और 'क्रांति' की। सिने पर्दे पर इन दोनों बेमिसाल अभिनेताओं की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। मनोज कुमार ने कई सुपर हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान देशभक्ति वाली फिल्मों से मिली। देश प्रेम, साम्प्रदायिक सद्भावना, एकता और भाईचारे का संदेश देने वाली फिल्में उनका ट्रेडमार्क बन गईं।

राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 'शहीद' को 'नर्गिस दत्त पुरस्कार', तो 'उपकार' के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने मनोज कुमार को साल 1992 में 'पद्मश्री सम्मान' से नवाज़ा है। बढ़ती उम्र और शारीरिक अस्वस्थता के चलते, भले ही एक लंबे अरसे से मनोज कुमार फिल्मों से दूर हों, लेकिन उनकी पुरानी फिल्में और सदाबहार गाने देशवासियों को आज भी रोमांचित करते हैं। उनमें देशभक्ति का जज्बा जगाते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

आम बजट-2024-25 में केंद्र सरकार ने गठबंधन को साधा मदद की 'गांठ' से

खास पैकेज : बिहार को 'विशेष राज्य' की तरह विकसित करेगी मोदी सरकार

■ अमृतकाल में धनवर्षा योग ■ 26 हजार करोड़ रुपए से विकसित होगा इन्फ्रास्ट्रक्चर
■ 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ से निपटने के लिए ■ 21 हजार करोड़ रुपए से होगी पवार प्लांट की स्थापना

बेधड़क | नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के इनकार के एक दिन बाद मंगलवार को बजट 2024-25 में राज्य को 'विशेष' बना दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने केंद्र राजग सरकार 3.0 का पहला बजट पेश करते हुए बिहार के विकास की रूपरेखा विशेष रूप से रखी। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार को रोड और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 26 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने 21 हजार करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार बिहार में कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने पूर्वोदय योजना की घोषणा 'बिहार' के नाम के साथ की। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय योजना लाई जा रही है, जिसमें

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध प्रदेश को भी रखा गया है। इन राज्यों में मानव संसाधन विकास, आधारभूत संरचना विकास और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार विशेष मेहनत करेगी। इन राज्यों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए केंद्र सरकार कृत-संकल्पित है।

बार -बार लिया बिहार का नाम

बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने बार बार बिहार का नाम लिया। बिहार को पूर्वोदय योजना में शामिल करने के अलावा एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, सड़क आदि के लिए बिहार का नाम कई बार लिया गया। जिन योजनाओं में बिहार को शामिल किया गया या जिससे बिहार को फायदा मिलना है, उसमें 'बिहार' पर जोर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भी वित्त मंत्री का स्वागत किया।

गया व बोध गया में बनेंगे कॉरिडोर

गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाकर धार्मिक पर्यटन विकसित किया जाएगा। नालंदा को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी। अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर केंद्र सरकार बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। इससे पूर्वी क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी।

बिहार को क्या-क्या मिला

दो एक्सप्रेस वे का विकास होगा

- राज्य में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 26 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे गया, नालंदा, दरभंगा समेत कई जिलों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे बनाने के लिए फंड देने का ऐलान किया है।

बनेंगे हाई वे-गंगा पर दो लेन वाला पुल बनेगा

- इसके अलावा बक्सर से भागलपुर के बीच भी एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। साथ ही बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाइवे बनेगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का एक पुल बनाया जाएगा।

2400 मेगावाट के एक नए संयंत्र की स्थापना

- इसके साथ ही, बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई, जिनमें भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है।

क्या है राजनीतिक गणित

- केंद्र की भाजपा नीत राजग सरकार के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी
- जद यू अहम सहयोगी दल है और सरकार के निर्बाध चलने के लिए नीतीश का साथ भी जरूरी है।
- बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एनडीए ने सरकार बनाई थी। बीच में नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे। इस साल 28 जनवरी को वापस आए और जदयू ने लोकसभा चुनाव राजग के तहत लड़ा। भाजपा-जदयू को बिहार से लोकसभा में बराबर सीटें मिलीं, लेकिन इस बार केंद्र में बनी राजग सरकार के लिए जदयू एक जरूरी घटक है।

क्या थी जद यू की मांग

- जदयू ने विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग साफ तौर पर कर दी थी।
- केंद्र ने पूर्वोदय योजना से साधा बिहार को
- विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान नीति आयोग के गठन के बाद नहीं होने की जानकारी सदन में देने के अगले दिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 'पूर्वोदय' के तहत बिहार के विकास की योजना लाकर एक तरह से जदयू की मांग पूरी कर दी।

हम खुश हैं, बिहार को काफी मदद मिली, कई घोषणाएं हुईं

पटना। मोदी सरकार के आम बजट को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बजट से हम खुश हैं। राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे थे। हमने कहा था कि विशेष राज्य जा दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद कीजिए। अब कई चीजों

की मदद की घोषणा हुई है। आज जो बोल रहे हैं जब उनकी पार्टी केंद्र में थी तब क्या किए? हम इसके लिए लगातार बोलते रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को केंद्र सरकार की ओर से पूरी मदद मिल रही है। विशेष राज्य का दर्जा बंद कर दिया, तो जो मदद होनी चाहिए थी। वो विकास के लिए हो रही है। उन्होने कहा कि पहले बिहार का बुरा हाल था। अब कितना रास्ते, रोड और स्कूल बन गए हैं। पटना में कितना काम हुआ है। वहीं बिहार विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्षी दल के नेता झुनझुना लेकर सदन पहुंचे। इस बीच नीतीश सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा विपक्ष को घेरा और जमकर निशाना साधा। चौधरी ने कहा कि बिहार को अब तक किसी भी बजट में इतनी मदद कभी नहीं मिली थी। उन्होने कहा कि एक और केंद्र के बजट में बिहार का डंका बज रहा है। वहीं, विपक्ष के लोग विशेष राज्य के दर्जे का झुनझुना बजा रहे हैं। विपक्ष को अगर बिहार के विकास में जरा भी रुचि होती, तो प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के प्रति आभार जता रहे होते। दरअसल, संसद में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने वित्त मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार के पास बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की कोई योजना है।

बजट और सवालों के जवाब

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नई दिल्ली में बजट पेश किया। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान सहित कई देशों को मिलेगी सहायता

भूटान को 2,068.56 करोड़ रुपए की मिलेगी मदद

बेधड़क | नई दिल्ली

केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत ने भूटान समेत कई पड़ोसी देशों को सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसमें भूटान को सबसे ज्यादा सहायता राशि 2,068.56 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। यह राशि पिछले साल के 2,400 करोड़ रुपए से कम है। भूटान को बाद भारत नेपाल को सबसे ज्यादा सहायता प्रदान की जाएगी। दस्तावेजों के मुताबिक भारत मालदीव को पिछले साल के बराबर ही 400 करोड़ रुपए मिलेंगे। हालांकि, वित्त वर्ष 2023-2024 के संशोधित बजट में यह राशि 770.90 करोड़ रुपये थी। भूटान, नेपाल और मालदीव के अलावा भारत कई अन्य देशों को भी सहायता प्रदान करेगा. इनमें श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं।

राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन

आंध्र के लिए खोला खजाना... पैकेज की मांग पूरी

बेधड़क | नई दिल्ली

वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के लिए ऐलान किया कि अमरावती में राजधानी तैयार करने के लिए राज्य को 15 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य का पुनर्गठन हुआ है और उसकी माली हालत पहले जैसी नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। हर मोर्चे पर आंध्र के विकास के लिए योगदान दिया जाएगा। इसके अलावा गोदावरी नदी पर बनी पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए भी योगदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए यह स्कीम जीवनरेखा की तरह है। इससे किसानों को मदद मिलेगी और राज्य की खाद्य सुरक्षा भी तय होगी। उन्होंने कहा कि हम इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के प्रयास करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में रायलसीमा के पिछड़े इलाकों और उत्तरी जिलों के विकास के लिए भी फंड आवंटित होंगे। उन्होंने आंध्र पुनर्गठन एक्ट के तहत जो वादा किया गया था, उसके तहत राज्य में औद्योगिक इकाइयों को

भी विकसित किया जाएगा। मोदी सरकार के बजट में वादा किया गया है कि विशाखापत्तनम-चेन्नै इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा हाईवे, सड़कों, बिजली और पानी के लिए भी पर्याप्त फंड जारी होगा। अनुमान है कि आंध्र को कुल मिलाकर 50 हजार करोड़ रुपए का सीधा लाभ मिलेगा।

इन परियोजनाओं को भी मिलेगी मदद

- गोदावरी नदी पर बहुप्रतीक्षित पोलावरम सिंचाई परियोजना।
- रायलसीमा, प्रकाशम और तटीय आंध्र को विकसित करने के लिए मदद। -विशाखापटनम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।
- आर्थिक विकास के लिए पूंजी निवेश के लिए इस वर्ष अतिरिक्त आवंटन।

स्पेशल पैकेज के लिए दो बार दिल्ली आए थे नायडू

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी और राज्य के विकास के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की थी। चंद्राबाबू नायडू पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी मिले थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि मोदी सरकार को समर्थन दे रही तेलगूदेशम पार्टी की मांग पूरी की जाएगी।

खुश हुई TDP, नायडू बोले-पीएम मोदी को धन्यवाद

अमरावती। आंध्र प्रदेश को वर्ष 2024-25 के बजट में मिली सौगातों पर राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रसन्ना जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं दी। नायडू ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमारे राज्य की जरूरतों को पहचानने और वित्त वर्ष 24-25 के केंद्रीय बजट में राजधानी, पोलावरम, औद्योगिक नोड्स और प्रदेश पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्र का यह समर्थन बहुत आवश्यक था। न्होंने आगे लिखा कि आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में इस राशि से काफी मदद मिलेगी। इस प्रगतिशील और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले बजट की प्रस्तुति के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने अमरावती और पोलावरम सिंचाई परियोजना को समर्थन प्रदान करने वाले केंद्र सरकार के बजटीय प्रस्तावों का स्वागत किया। उन्होंने कहा, राज्य की जनता की ओर से हम एनडीए सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिसने बजट में 15 हजार करोड़ रुपए आवंटित करके आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है।

जम्मू-कश्मीर को मिले 42 हजार 277 करोड़

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश केंद्रीय बजट में जम्मू-कश्मीर को 42 हजार 277 करोड़ रुपए आवंटित गए। यह पिछले वित्त वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए 41 हजार 751 करोड़ रुपए से 1.2% अधिक है। हालांकि इस बार जम्मू-कश्मीर पुलिस को 9 हजार 789 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड भी दिया गया है। यह राशि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ ही जनकल्याण कार्यक्रमों और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए की जा रही पहल पर खर्च होगी क्योंकि यह राज्य भी चुनाव की तैयारियों में जुटा है। अब, राज्य का बजट संसद में पेश होना बाकी है, जो संभवत: संसद में पेश होने वाला जम्मू कश्मीर का आखिरी स्टेट बजट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सितंबर 2024 से पहले राज्य में विधानसभा चुनाव करवाने का आदेश दे चुका है। जम्मू कश्मीर में पिछली बार विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2014 में हुए थे। तब पीडीपी-भाजपा की गठबंधन सरकार बनी थी। जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सदन होने के बाद बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा।

लद्दाख के बजट में 32% की वृद्धि : केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषित केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछले साल के 4,500 करोड़ रुपए के आवंटन से 32 प्रतिशत अधिक है। साल 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर से अलग हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अपने सचिवालय से संबंधित खर्चों और अन्य विभागों और कार्यालयों की स्थापना के लिए केंद्र से स्थापना एक्सपेंडिचर के लिए 2,035.49 करोड़ रुपए मिले हैं। बजट में लद्दाख को अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय के लिए 3,922.51 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

चुनावी राज्य: महाराष्ट्र का नाम तक नहीं आया

महाराष्ट्र: आम बजट में नरेंद्र मोदी सरकार में गठबंधन वाली पार्टियों की सत्ता वाले आंध्र प्रदेश और बिहार का जिक्र तो आया लेकिन महाराष्ट्र का एक बार भी नाम नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुती सरकार इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत कायम रखना चाहती है। महायुती में भाजपा के साथ-साथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के धड़े वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शामिल है।

झारखंड: निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में झारखंड का नाम तो लिया लेकिन पूर्वी भारत के समग्र विकास के संबंध में जिक्र भर था। झारखंड में इंडिया ब्लॉक की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सरकार है। सीतारमण ने कहा कि पूर्वोदय के तहत इन राज्यों में मानव संसाधन विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास के अवसरों के सृजन पर काम किया जाएगा ताकि विकसित भारत में पूर्वी भारत के राज्य इंजिन बन सके।

हरियाणा: महाराष्ट्र की ही तरह हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है लेकिन केंद्रीय बजट में इसका जिक्र तक नहीं किया गया।

पूर्वोदय योजना में ओडिशा, प. बंगाल व झारखंड भी

पूर्वोदय योजना, जिसे सरकार ने विकास भी विरासत भी नाम दिया है, के तहत जिन पांच पांच राज्यों को शामिल किया है, उनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साथ झारखंड भी है। इन पांच राज्यों में गौर करें तो इनमें ओडिशा में भाजपा की सरकार बन चुकी है। लिहाजा प्रदेश को सरकार ने तोहफा दिया है। बिहार और आंध्र प्रदेश को गठबंधन समझौते के तहत तवज्जो देना लाजिमी था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि इनमें पश्चिम बंगाल को भी शामिल किया गया है, जहां निकट भविष्य कोई चुनाव नहीं है।

तेलंगाना के सांसद दर्ज करवाएंगे विरोध

आंध्र को मिला 'स्पेशल पैकेज' तो भड़के तेलंगाना के सीएम

बेधड़क| हैदराबाद

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को केंद्रीय बजट को लेकर निराशा जताई और आरोप लगाया कि इसमें तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 8 कांग्रेस सांसद इस बजट में तेलंगाना की अनदेखी को लेकर विरोध दर्ज कराएंगे। इस विरोध प्रदर्शन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद भी भाग ले सकते हैं। सीएम रेड्डी ने आंध्र प्रदेश को बजट में 'स्पेशल पैकेज' दिए जाने पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि आंध्र के साथ

तेलंगाना को भी विशेष आवंटन दिया जाना चाहिए था। तेलंगाना के सीएम ने कहा, हमारे 8 कांग्रेस सांसद निश्चित रूप से अन्य सांसदों के साथ अपना विरोध व्यक्त करेंगे। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम केवल आंध्र प्रदेश के लिए फंड देने के बारे में नहीं है, बल्कि तेलंगाना के बारे में भी है।

बीआरएस ने भी जताई निराशा

इससे पहले भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी.रामाराव ने भी केंद्रीय बजट को लेकर निराशा जताते हुए कहा कि इसमें तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि 48 लाख करोड़ रुपये का बजट होने के बावजूद केवल कुछ राज्यों को इसका लाभ मिला है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्तवर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया। नरेन्द्र मोदी नीत सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला केंद्रीय बजट है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट में से आठ-आठ पर भाजपा एवं कांग्रेस की जीत का संदर्भ देते हुए रामाराव ने कहा कि लोगों को सोचना होगा कि जब वे दो राष्ट्रीय दलों को 16 सीट देते हैं तो क्या होता है। इस लोकसभा चुनाव में बीआरएस को तेलंगाना में एक भी सीट नहीं मिली है। रामा राव ने कहा कि बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव जब मुख्यमंत्री थे तो केंद्र से अनुरोध किया था कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में तेलंगाना से किए गए लगभग 35 'वादों' को पूरा करने का निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि अनुरोध के बावजूद राज्य में किसी भी सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया गया है।

जनता भाजपा को सिखाएगी सबक

रामा राव ने कहा, मौजूदा मुख्यमंत्री और तेलंगाना के मंत्रियों ने दिल्ली दौरे के दौरान कई अनुरोध किए थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। तेलंगाना को इस केंद्रीय बजट में कुछ भी नहीं मिला है। तेलंगाना के लोगों को आंध्र प्रदेश और बिहार को आवंटित धनराशि पर गौर करना चाहिए जहां संसद की अधिक सीटें हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता आठ सांसद होने के बावजूद कोई धन आवंटित नहीं करने का सबक भाजपा सरकार को सिखाएगी।

जरूरी खबर

जमानत पर सोच समझकर लगाएं रोक: SC

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए एक अहम टिप्पणी की। सर्वोच्च अदालत ने कहा, कोर्ट को स्टे लगाने का अधिकार होता है, लेकिन किसी की जमानत पर यूं ही रोक नहीं लगाई जा सकती। सिर्फ असामान्य मामलों और असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा करना चाहिए। हाईकोर्ट को ऐसे मामलों में सोच समझकर फैसला देना चाहिए। सामान्य तौर पर हाईकोर्ट को जमानत के आदेशों पर रोक नहीं लगानी चाहिए। जस्टिस अभय सिंह ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी परविंदर सिंह खुराना की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। परविंदर खुराना को ईडी ने 2023 में गिरफ्तार किया था। बाद में जून 2023 में उन्हें ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके खिलाफ ईडी हाईकोर्ट पहुंची, तो हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया।

प्रदीप भंडारी होंगे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता

नई दिल्ली। भाजपा ने प्रदीप भंडारी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह नियुक्ति की है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने यह जानकारी दी है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। प्रदीप भंडारी का मीडिया में लंबा कॅरियर रहा है। भाजपा के कुल 30 राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिनका नेतृत्व राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी करते हैं। प्रदीप भंडारी इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी पर एक पुस्तक भी लिख चुके हैं।

INS ब्रह्मपुत्र : आग से नुकसान का आकलन

पणजी। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने मंगलवार को कहा कि आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर आग लगने से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। साथ ही लापता नाविक की तलाश जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि रविवार को आग लगने के बाद लापता हुए नाविक को जहाज से बाहर निकलते देखा गया है और सभी की तलाश जारी है। गौरतलब है कि 21 जुलाई की शाम को मल्टी-रोल फ्रिगेट में आग लग गई थी। जहाज के चालक दल ने अग्निशमन कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया। हालांकि, आग लगने के बाद जहाज एक तरफ ही झुका रहा गया और तमाम कोशिशों के बावजूद उसे सीधा नहीं किया जा सका।

चलें बजट पेश करने ... वित्त मंत्री अपनी टीम के साथ

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बजट पेश किया। इससे पहले वह नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी व अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ संसद भवन के लिए रवाना हुईं। वे राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन भी पहुंची। रवानगी से पहले अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री सीतारमण।

अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की प्रमुख ने दिया इस्तीफा

वॉशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को रोकने में नाकाम रहने पर सीक्रेट सर्विस की निदेशक किंबरले चीटल ने इस्तीफा दे दिया है। चीटल ने कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में अपने पद से इस्तीफा देने की जानकारी दी है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की जिम्मेदारी वर्तमान राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा करना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर हमला न रोक पाने के कारण सीक्रेट सर्विस की आलोचना हुई। वहीं जिस दिन ट्रंप पर हमला हुआ उसी दिन सोशल मीडिया पर किंबरले के इस्तीफे की मांग उठी थी। उनका इस्तीफा सोमवार को संसद में पेशी के बाद आया है। हाउस ओवरसाइट कमेटी के समक्ष तनावपूर्ण और विवादास्पद सुनवाई के एक दिन बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया।

NEET-UG पेपर लीक केस : 4 लाख छात्रों की मार्किंग में बदलाव संभव

दोबारा नहीं होगी परीक्षा, NTA फिर से जारी करे रिजल्ट: SC

एजेंसी | नई दिल्ली

नीट-यूजी पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यह परीक्षा दोबारा नहीं कराई जा सकती क्योंकि बड़ी गड़बड़ी साबित नहीं हो सकी है। कोर्ट ने कहा कि फिर से परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा और यह 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्वांटम फिजिक्स के एक सवाल के विकल्प 4 को सही ठहराते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से दोबारा रिजल्ट घोषित करने को कहा। दोबारा रिजल्ट जारी होने से 4 लाख छात्रों की मार्किंग में बदलाव देखने को मिलेगा।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने कहा कि इस मामले में व्यवस्थागत खामी की बात साबित नहीं होती है। इसलिए दोबारा से परीक्षा कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने फिजिक्स के विवादित सवाल पर कहा कि उसका सही जवाब विकल्प 4 है। अदालत ने कहा, फिर से परीक्षा कराने का आदेश देना 24 लाख बच्चों के

आज से शुरू हो जाएगी नीट की काउंसिलिंग

कोर्ट के इस आदेश के बाद अब बुधवार से नीट यूजी की काउंसिलिंग शुरू हो जाएगी। अदालत ने कहा कि पेपर लीक की बात हजारीबाग में ही साबित हो पाई है। इस मामले में व्यवस्थागत लीक की बात साबित नहीं हो सकी है। ऐसे में परीक्षा को रद्द करने की मांग सही नहीं है।

कमेटी ने बताया चौथा विकल्प सही

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने भौतिकी विभाग से एक समिति गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट हमें मिल गई है. तीन विशेषज्ञों की समिति ने कोर्ट को बताया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पूछे गए भौतिकी के विवादास्पद प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर था, न कि दो। सीजेआई ने कहा कि विशेषज्ञ दल का मानना है कि विकल्प चार सही है और कथन 2 गलत है क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थ के परमाणु स्थिर नहीं होते हैं। इसलिए एनटीए ने अपनी उत्तर कुंजी में सही कहा कि विकल्प 4 सही था।

NTA रिजल्ट का फिर से कर लेगा मिलान

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि एनटीए इस विकल्प के आधार पर रिजल्ट का फिर से मिलान कर लेगा। अदालत ने कहा कि एनटीए ने 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा भी कराई थी। उन लोगों को विकल्प मिला था कि ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे और यदि वे चाहें तो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। यह भी विकल्प था कि जो बिना ग्रेस मार्क्स के ही मेरिट का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे चाहें तो परीक्षा न भी दें।

LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम

पुंछ में सेना व आतंकियों में मुठभेड़, जवान शहीद

एजेंसी | श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सेना ने मंगलवार तड़के नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी।हालांकि, इस दौरान मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। शहीद की पहचान उत्तर प्रदेश स्थित हाथरस निवासी सुभाष के तौर पर हुई है। सूत्रों के मुताबिक, हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने कृष्णाघाटी बेल्ट के बट्टल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सतर्क सैनिकों ने उनकी गतिविधियों को भांप लिया और त्वरित कार्रवाई की। जम्मू स्थित सेना के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने कहा, अलर्ट सैनिकों ने मंगलवार तड़के 3 बजे कृष्णा घाटी इलाके में बट्टल सेक्टर में ताबड़तोड़ गोलीबारी के साथ घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों को प्रभावी ढंग से घेरकर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। भारी

गोलीबारी के दौरान एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि इलाके में तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले 'व्हाइट नाइट कॉर्प्स' ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, सतर्क सैनिकों ने तड़के तीन बजे बट्टल सेक्टर में घुसपैठ की फिराक में जुटे आतंकवादियों की गोलीबारी का माकूल जवाब देकर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। इसमें एक जवान घायल हो गया था। सूत्रों के अनुसार, गोलीबारी में आतंकवादियों को भी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि इलाके में तलाश अभियान चलाया जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के पास जाएगा अब मामला

GM सरसों पर SC ने दिया खंडित फैसला

एजेंसी | नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने सरसों की संकर (हाइब्रिड) किस्म डीएमएच-11 को बीज उत्पादन और परीक्षण के लिए पर्यावरण में छोड़ने के केंद्र सरकार के वर्ष 2022 के फैसलों की वैधता पर मंगलवार को खंडित फैसला सुनाया। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने जीएम सरसों को पर्यावरण में छोड़े जाने की सिफारिश करने के जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) के 18 अक्टूबर, 2022 के फैसले और उसके बाद 25 अक्टूबर, 2022 को सुनाए गए 'ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड डीएमएच-11' को पर्यावरण में छोड़े जाने संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। जीईएसी आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) जीवों के लिए देश की नियामक संस्था है। इस मामले में दलीलें सुनने के बाद पीठ ने अलग-अलग राय दी। पीठ ने इस मामले को प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखे जाने का निर्देश दिया, ताकि कोई दूसरी पीठ इस पर फैसला दे सके। हालांकि, दोनों न्यायाधीशों ने आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का केंद्र को एकमत से निर्देश दिया।

जीईसी के फैसले पर बंटी राय

जस्टिस नागरत्ना ने जीएम फसलों को पर्यावरण में छोड़े जाने के मुद्दे पर कहा कि 18 और 25 अक्टूबर, 2022 को दिए गए जीईएसी के निर्णय दोषपूर्ण थे, क्योंकि बैठक में स्वास्थ्य विभाग का कोई सदस्य नहीं था और कुल आठ सदस्य अनुपस्थित थे। दूसरी ओर, जस्टिस करोल ने कहा कि जीईएसी के फैसले किसी भी तरह से मनमाने और गलत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जीएम सरसों फसल को सख्त सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए पर्यावरण में छोड़ा जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कार्यकर्ता अरुणा रोड्रिग्स और गैर-सराकारी संगठन 'जीन कैंपेन' की अलग-अलग याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया।

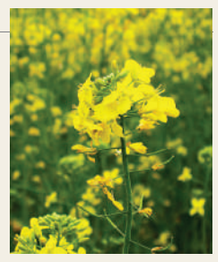

महिला एशिया कप: शेफाली का अर्द्धशतक

नेपाल को हरा भारत सेमीफाइनल में

एजेंसी | दांबुला (श्रीलंका)

महिला एशिया कप 2024 में भारत का विजय अभियान जारी है। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने नेपाल को 82 रनों से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब उसका सामना ग्रुप बी की शीर्ष टीम से 26 जुलाई को होगा।

ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। दोनों टीमें इस ग्रुप में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहीं। भारत ने ग्रुप स्टेज पर लगातार तीन मैचों में जीत दर्ज की जबकि पाकिस्तान को सिर्फ दो मुकाबलों

में जीत मिली। भारत के खाते में अब छह अंक हो गए हैं और उनका नेट रनरेट +3.615 है। वहीं, पाकिस्तान के खाते में चार अंक और नेट रनरेट +1.102 है।

दांबुला के रणगिरि दांबुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में तीन विकेट पर 178 रन बनाए। शेफाली वर्मा और दयालन हेमलता ने पहले विकेट के लिए 122 रनों की साझेदारी हुई। हेमलता 42 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हुईं। वहीं, शेफाली ने 26 गेंदों में मौजूदा टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक लगाया। वह 48 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हुईं। जवाब में नेपाल 20 ओवर में नौ विकेट पर 96 रन ही बना सकी। भारत ने यह मैच 82 रनों से जीत लिया। मौजूदा टूर्नामेंट में यह भारत की लगातार तीसरी जीत है।

टाटा-एयरबस हेलिकाप्टर्स के बीच समझौता

भारत में आठ शहरों में होगा एच-125 हेलिकॉप्टर का निर्माण

एजेंसी | नई दिल्ली

टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस हेलिकॉप्टर्स के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसके तहत एच 125 हेलिकॉप्टर्स को तैयार करने के लिए भारत में फाइनल एसेंबली लाइन (एफएएल) को स्थापित किया जाएगा। कंपनी ने इसके लिए देश के आठ शहरों को चुना है। कंपनी इन शहरों में दूसरे प्लांट यानी चौथी असेंबली लाइन की स्थापना की योजना बना रही है। अगले कुछ दिनों में ही कंपनी की पहली असेंबली लाइन का उद्घाटन होना है। ज्ञात रहे कि असेंबली लाइन एक उत्पादन प्रक्रिया है, जिसके

तहत वस्तुओं के निर्माण को अलग अलग चरणों में विभाजित किया जाता है।

एयरबस की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार एफएएल के लिए भारत में हेलिकॉप्टर असेंबली सुविधा स्थापित करने का यह पहला उदाहरण होगा। हेलिकॉप्टर असेंबली सुविधा स्थापित करने से देश में ही इस हेलिकॉप्टर का निर्माण संभव हो सकेगा। एयरबस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑलिवर मिशलॉन ने बताया है कि हमने फिलहाल भारत में आठ ऐसे शहरों को चिह्नित किया है जहां पर आखिरी असेंबली लाइन को खोलने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल कंपनी इसका मूल्यांकन कर रही है। उन्होंने अपने बयान में उन शहरों के बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन यह कहा कि वह जल्द ही इसकी घोषणा कर सकते हैं। गौरतलब है कि एयरबस कंपनी का यह चौथा प्लांट होगा जहां सिंगल-इंजन के हेलिकॉप्टर का निर्माण होगा। इससे पहले कंपनी के प्लांट अमेरिका, फ्रांस और ब्राजील जैसे देशों में रहे हैं।

भारतीय उपमहाद्वीप में है मांग

एयरबस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भारतीय उपमहाद्वीप पर ऐसे हेलिकॉप्टरों की भारी मांग होगी। ऑलीवर ने यह भी कहा कि भारत में निर्मित होने वाले हेलिकॉप्टर न सिर्फ कम समय में बनेंगे बल्कि यह आसपास के पड़ोसी देशों की डिमांड को भी पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि एच 125 हेलिकॉप्टर भारत में ए320 एयरबस के समान ही सफल होंगे। भारत के गुजरात के वडोदरा में एयरबस की पहली असेंबली साइन लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें एयरफोर्स के लिए सी-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा.।

पहला हेलिकॉप्टर 2026 में होगा तैयार

टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुकरन सिंह ने कहा, यह कदम मेक इन इंडिया के तहत भारत के बढ़ते हेलिकॉप्टर बाजार की ओर भी इशारा करता है। इस कार्ययोजना से भारत में हेलिकॉप्टर निर्माण की क्षमता भी विकसित होगी। उन्होंने दावा किया कि भारतीय ग्राहकों के साथ साथ पड़ोसी देशों को भी एफएएल द्वारा तैयार किए गए हेलिकॉप्टर दिए जाएंगे। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि स्वदेश में निर्मित भारत का पहला एच 125 हेलिकॉप्टर 2026 में तैयार हो जाएगा।

फार्नबरो एयरशो 2024 में किए गए थे अनुबंध पर हस्ताक्षर

इस वर्ष 26 जनवरी को एयरबस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिलाउम फाउरी और टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर ने भारत में एफएएल की स्थापना की घोषणा की थी। इससे जुड़े अनुबंध पर फार्नबरो एयरशो 2024 में हस्ताक्षर किए गए थे।

वित्त मंत्री ने मनोरंजन जगत के लिए नहीं की कोई घोषणा

उम्मीद पर आघात... एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं घटाए जाने से बॉलीवुड में छाई निराशा

बेधड़क. जयपुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश किया। इसमें मनोरंजन जगत के लिए कोई घोषणा नहीं होने से बॉलीवुड सेलेब्स में मायूसी है। ऐसा माना जा रहा था कि सरकार इस बार एंटरटेनमेंट टैक्स में कमी कर सकती है, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। मौजूदा समय में फिल्म का टिकट 100 रुपए से कम है तो उसपर 12% जीएसटी लगता है, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा प्राइज वाली टिकट का जीएसटी स्लैब अलग है और इसपर 18% जीएसटी वसूला जाता है।

हमेशा इग्नोर की जाती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री

शेरशाह, मिशन इस्तांबुल और लूट जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर रहे शब्बीर बॉक्सवाला ने कहा कि बजट सिर्फ गरीबों के लिए ही होता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। ऐसा लगता है कि बजट हमेशा गरीबों पर फोकस होता है, इसमें अमीरों पर कोई फोकस नहीं होता, जबकि वही गरीबों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। सरकार मनोरंजन जगत को हमेशा ओवरलुक करती है, जबकि एक प्रोड्यूसर किसी फिल्म के जरिए 300 से ज्यादा परिवारों को रोजगार देता है। सरकार इतने बड़े लेवल पर कहां रोजगार दे पा रही है। जिस तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल रही है, बहुत बुरा हाल है। थिएटर बंद हो चुके हैं, ऐसे में सरकार को मदद करनी चाहिए थी। फिल्म प्रोड्यूसर सुनील दर्शन ने कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। सरकार मनोरंजन जगत के पहलुओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है।

जीएसटी खत्म किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया

सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और फिल्म प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी ने कहा कि फिल्मों के टिकट पर लगने वाले जीएसटी को खत्म किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहलाज निहलानी बोले, बहुत से देशों में एंटरटेनमेंट पर टैक्स नहीं है इसलिए जीएसटी को इंडिया में भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से पूरी तरह हटाना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि अपने कल्चर और भाषा को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फिल्में बनाने की कोशिशों को बढ़ावा दिया जाए।

सिंगल स्क्रीन सिनेमा को मिलता बूस्ट अप

मौजूदा समय में जिस तरह का बिजनेस आ रहा है, उसकी वजह से अच्छे विषयों पर फिल्में नहीं बन पा रही हैं और पैसे कमाने के लिए हल्के विषयों और वल्गर कंटेंट पर फिल्में बनने की मजबूरी हो गई है। निहलानी ने आगे कहा कि फिल्में कॉमन मैन के लिए बनती हैं। छोटे से छोटा मजदूर भी क्चर देखता है, अगर फिल्म टिकट सस्ती हो जाए और इस पर टैक्स न लगे तो इससे सिंगल स्क्रीन सिनेमा को बूस्ट अप मिलेगा।

फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी भी कई चीजें हैं देश में

कभी हां कभी ना, चक दे इंडिया समेत 127 फिल्मों में काम कर चुके एक्टर अंजन श्रीवास्तव ने कहा कि बजट जब भी होता है, अच्छा ही होता है। देश में विकास हो रहा है, सड़कें, फ्लाईओवर बन रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिहाज से कोई बड़े बदलाव बजट में देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन देश में फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी भी कई चीजें हैं जो जरूरी हैं।

कथक में हुआ मयूर और प्रकृति का सौंदर्य साकार

बेधड़क. जयपुर। जवाहर कला केन्द्र की सहभागिता में आयोजित छह दिवसीय नटराज महोत्सव की मंगलवार को संगीतमय शुरुआत हुई। युवा रंगकर्मियों के संयुक्त प्रयास ने साकार रूप लिया। महोत्सव के पहले दिन जयपुर घराने की कथक नृत्यांगना मनीषा गुलयानी ने समां बांधा। महोत्सव निदेशक योगेन्द्र सिंह ने अन्य युवा कलाकारों के साथ नटराज को माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर महोत्सव की विधिवत शुरुआत की। मनीषा गुलयानी की कथक प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा। नृत्य श्लोक से आगाज करने के बाद मनीषा ने कथक के जरिए शिव तांडव स्रोत पर शिव और शक्ति की स्तुति की। ताल धमार में 14 मात्रा में विलंबित बंदिश पर फुटवर्क और आंगिक अभिनय का उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। इसके बाद राग चारुकेसी में द्रुत तीन ताल में निबद्ध बंदिश पर नृत्य करते हुए मयूर और प्रकृति के सौंदर्य को साकार किया। मनीषा ने पारंपरिक कथक में तोड़ा, परण, परमेलू, कवित्त और गत पेश की। हारमोनियम पर पं. राजेन्द्र प्रसाद बनर्जी, तबले पर मो. शोएब, तनपुरे पर मो. उस्मान और अयान खान ने संगत की। बता दें कि महोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को शाम सात बजे रंगायन में नाटक 'द शैडो ऑफ ओथेलो' का मंचन होगा।

जयपुर के तुषार का चयन

बेधड़क. जयपुर। राजधानी निवासी तुषार का भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग प्रोत्साहन योजना में सेमीकंडक्टर विनिर्माण में भारत-अमेरिका क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में चयन किया गया। कार्यक्रम में सहभागिता के लिए अखिल भारतीय स्तर पर 20 का चयन हुआ है। तुषार वर्तमान में एमएनआईटी जयपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के तृतीय वर्ष में हैं। 2 अगस्त तक पर्ड्यू विश्वविद्यालय इंडियाना संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्नत प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए शिकांगो संयुक्त राज्य अमेरिका रवाना हुए।

गुरु का महत्व बच्चों को जन्म से ही सिखाते रहें

बेधड़क. जयपुर। पशुपति नाथ मंदिर मुहानासिद्ध पीठ धाम के संत कमलेश के सान्निध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन मानसरोवर स्थित 'मैजेस्टिक रेसोर्ट' में मंगलवार को किया गया। प्रवक्ता नीरज और मोहित ने बताया कि कार्यक्रम में भजन संध्या और प्रसादी का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत कमलेश ने कहा कि इस देश के संस्कार रहे हैं कि माता-पिता जन्म से ही बच्चों का संबंध किसी न किसी रूप में गुरु से जोड़ते रहे हैं। चाहे वह गुरु शिक्षा के क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, या जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के क्षेत्र में हो, यह देश की परंपरा का हिस्सा रहा है और यहां गुरु सर्वोपरि रहे हैं। फिल्म निर्माता व निर्देशक अमित बोकाड़िया मुंबई से गुरु कमलेश की गुरु वंदना करने जयपुर आए एवं आशीर्वाद लिया। बोकाड़िया ने बताया कि सिद्धपीठ धाम पशुपतिनाथ मंदिर, मुहाना से मेरा पुराना नाता है। हर साल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं यहां मुंबई से गुरु वंदना के लिए आता हूं।

गायों को पहुंचाएंगे भोजन

बेधड़क. जयपुर। घरों से गाय के लिए रोटी, हरा चारा इकट्ठा किया जाएगा और गोशालाओं तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 'गो ग्रास वाहन' की शुरुआत की गई। बावलिया बाबा धाम और पीठाधीश्वर डॉ. पंडित राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में गो ग्रास योजना के राष्ट्रीय संयोजक भूपेन्द्र यादव, जयपुर जिलाध्यक्ष संदीप, मध्यप्रदेश संयोजक अशोक प्रजापति, कोटा जिलाध्यक्ष सौरभ मित्तल, प्रह्लाद शर्मा और अन्य सेवक उपस्थित रहे।

City इवेंट्स

मदद के लिए उठे हाथ तो खिल उठे चेहरे

बेधड़क. जयपुर। एक 14 का बच्चा ट्रेन एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया और उसका पैर व बाजू डेमेज हो गई। उसकी सर्जरी होनी थी तो हमने क्राउंड से मांग की और उसका इलाज कराया। फिर इसी सेवा का कारवां आगे बढ़ता गया और अब हम पूरे देश में लोगों की मदद से जन सेवा करते हुए मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ-साथ जानवरों की सेवा भी कर रहे हैं। जयपुर की बात की जाए तो यहां से हमारे साथ हजारों लोग जुड़ चुके हैं, जो जनसेवा में लगे हुए हैं। ये विचार मिलाप की वाइस प्रेसिडेंट मान्या शर्मा ने जयपुर में रखे। वे शहर में हुए इस मंच के प्रोग्राम में शिरकत कर रही थीं। उनके साथ रक्षा के अधिकारी और कुछ बनीफिशरी भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने-अपने अनुभव शेयर किए। वहां अपने बच्चे की परेशानी से जूझ रहे सागर भी आए और उन्होंने बताया कि इस मंच से हमें इलाज में फायदा हुआ। जयपुर से कैम्पेन के आयोजक अधिराज सिंह ने अपने डोमेस्टिक हेल्पर के बेटे के लिए धन जुटाने का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि 79 डोनर्स की उदारता की बदौलत हमने मनराज की सर्जरी के लिए 1.75 लाख रुपए से जुटाए, जिससे उनकी आंख बच गई।

जगदीश महाराज की पद यात्रा 28 को

बेधड़क. जयपुर। श्री लक्ष्मीपति जगदीश महाराज की 11वीं विशाल पद यात्रा 28 जुलाई को जाएगी। यात्रा तत्काली बालाजी का मंदिर डिग्गी रोड बालावाला से सुबह 6:15 बजे गोनेर के लिए प्रस्थान करेगी। यात्रा बालावाला स्टेशन, रिंग रोड, वाटिका रोड, कल्लावाला, 12 मील, विधानी होते हुए जगदीश महाराज धाम गोनेर पहुंचेगी। यात्रियों की लिए प्रसादी की व्यवस्था श्रीजगदीश महाराज सेवा समिति बालावाला की ओर से बागड़ा धर्मशाला में होगी। यात्रा में बड़ी संख्या में जयपुराइट्स के साथ ही आस-पास के गांव वाले हिस्सा लेंगे।

इंस्टालेशन सेरेमनी में कार्यकारिणी को शपथ

बेधड़क. जयपुर। रोटरी क्लब जयपुर रॉयल की इंस्टालेशन सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें नव निर्वाचित अध्यक्ष डॉ. रोहन गुप्ता और कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3056 के डिस्ट्रिक्ट लर्निंग फेसिलिटेटर व चीफ मेंटर डॉ. अशोक गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉ. राखी गुप्ता और गेस्ट ऑफ ऑनर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनेटेड अरुण बगड़िया, डीएसजी आलोक अग्रवाल व असिस्टेंट गवर्नर मोहनीश मेहरा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नए जुड़े सदस्यों का स्वागत कर उन्हें शपथ दिलाई गई। साथ ही क्लब की ओर से प्रायोजित रोटरैक्ट क्लब ऑफ राजस्थान डेंटल कॉलेज की इंस्टालेशन सेरेमनी की गई, जिसमें अरुण बगड़िया ने रोटरेक्ट्स को शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान प्रांत की आरएलआई (रोटरी लर्निंग इंस्टीट्यूट) समिति की पूनम बगड़िया ने आयोजक क्लब प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आरएलआई कार्यक्रम की तिथि की घोषणा करते हुए सेव द डेट पोस्टर का विमोचन किया।

निर्वाण विश्वविद्यालय में 26 को होगा पुस्तक पैनल का आयोजन

वैश्विक न्यूक्लियर सुरक्षा चुनौतियों पर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ करेंगे चर्चा

बेधड़क | जयपुर

निर्वाण विश्वविद्यालय में 26 जुलाई को 'भारत-अमेरिका न्यूक्लियर सुरक्षा पर दृष्टिकोण' पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक पैनल का आयोजन किया जाएगा। इस पैनल में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों और विद्वानों की भागीदारी होगी, जो न्यूक्लियर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करेंगे।

इस महत्वपूर्ण पैनल में मुख्य वक्ताओं में अमेरीका से डॉ. एस पॉल कपूर, नेवल पोस्टग्रेजुएट स्कूल के नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स विभाग के प्रोफेसर और स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हूवर इंस्टीट्यूशन के विजिटिंग फेलो रहेंगे। उन्होंने 2019 से 2021 तक अमेरिकी राज्य विभाग के पॉलिसी प्लानिंग स्टाफ में सेवा की है और उनकी प्रमुख पुस्तकें 'जिहाद एज ग्रैंड स्ट्रैटेजी' और 'डेंजरस डिटरेंट' शामिल हैं। साथ ही, नेवल पोस्टग्रेजुएट स्कूल में रिसर्च असिस्टेंट के रूप में कार्यरत मिस डायना व्यागर भी होंगी, जो दक्षिण एशिया में न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी और सुरक्षा पर गहन शोध कर चुकी हैं। उन्होंने 'द चैलेंजेज ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटीः यूएस और इंडियन पर्सपेक्टिव्स' का संपादन भी किया है।

इस पैनल में डॉ. आरके अरोड़ा भी शामिल होंगे, जो निर्वाण विश्वविद्यालय के वाइस चेयरमेन हैं। डॉ. अरोड़ा के अनुभव और दृष्टिकोण से यह पैनल न्यूक्लियर सुरक्षा पर गहन विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा, जो भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा मामलों पर सहयोग और समझौते को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही पुस्तक 'द चैलेंजेज ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटीः यूएस और इंडियन पर्सपेक्टिव्स' का विमोचन भी होगा।

राजस्थान पुलिस अकादमी और निर्वाण विश्वविद्यालय के चेयरमेन डॉ. एसएल सिहाग के सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है। डॉ. सिहाग ने बताया कि यह पैनल चर्चा दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग और समझ को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से, निर्वाण विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से अपने आपको एक प्रमुख शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया है, जो वैश्विक सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर गहन अध्ययन और विचार-विमर्श को बढ़ावा देता है।

धर्म सभा मीरा मार्ग के श्रीआदिनाथ भवन में उमड़े श्रद्धालु

धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी तपस्या

बेधड़क | जयपुर

'साधुओं के साथ श्रावकों के लिए वर्षा योग महत्वपूर्ण होता है। चातुर्मास की बड़ी उपलब्धि ज्ञान का प्रकाश हमारी आत्मा पर पड़ता रहे। अहिंसा धर्म की स्थापना करने के लिए साधु को चार माह एक स्थान पर रुकना पड़ता है।' ये विचार अर्हम योग प्रणेता मुनि प्रणम्य सागर ने श्रीआदिनाथ दिगम्बर जैन भवन में आयोजित चातुर्मासिक धर्म सभा में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जीवन में विजन होना चाहिए। बिना विजन के जीवन जीने का कोई मतलब नहीं।

तीर्थंकरों की राह का पालन करना चाहिए

तीर्थंकरों ने हमें राह दिखाई है, लेकिन उस राह का पालन करना हमारा कर्तव्य है। जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलता है। धैर्य के साथ ही आप सब कुछ पा सकते हैं। धैर्य की कमी होने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। धैर्य के साथ स्पीड मेंटेन करना ही जीवन मे सुख-शांति समृद्धि का प्रतीक है। भगवान महावीर स्वामी ने निरंतर चलते रहने को तप कहा है।

कथा वाचन की होगी शुरुआत

मुनि ने बताया कि जैन तीर्थंकरों की कथा वाचन शीघ्र शुरु किया जाएगा, जिसमें सर्व प्रथम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की कथा सुनाना चालू किया जाएगा। इससे पूर्व मनीष-रचना चौधरी व संगीतकार नरेन्द्र जैन के निर्देशन में आचार्य विद्यासागर महामुनिराज की संगीतमय पूजा की गई। आचार्य समय सागर महाराज व मुनि प्रणम्य सागर महाराज का अर्घ्य चढ़ाया गया। इस मौके पर समाजश्रेष्ठी उत्तम चन्द पाटनी, श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के कार्याध्यक्ष प्रमोद पहाड़िया, राजस्थान जैन युवा महासभा जयपुर प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जैन, प्रदेश महामंत्री विनोद जैन कोटखावदा, नरेन्द्र जैन, दर्शन बाकलीवाल, शीतल कटारिया व अजीत तोतूका ने आचार्य विद्यासागर और आचार्य समय सागर महाराज के चित्र का अनावरण किया।

जिनवाणी स्तुति के साथ धर्म सभा का समापन

इस मौके पर अध्यक्ष सुशील पहाड़िया, मंत्री राजेन्द्र सेठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील बैनाडा, कोषाध्यक्ष लोकेन्द्र पाटनी राजभवन वाले, उपाध्यक्ष तेज करण चौधरी, संयुक्त मंत्री मनोज जैन, संगठन मंत्री अशोक सेठी, सांस्कृतिक मंत्री जम्बू सोगानी सहित कमेटी सदस्य व महिला मण्डल की पदाधिकारियों ने सहभागिता निभाई। जिनवाणी स्तुति के साथ धर्म सभा का समापन हुआ। अब मीरा मार्ग के श्री आदिनाथ भवन पर बुधवार से प्रतिदिन सुबह 8:15 बजे धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा।

पोस्टल रजि. नं. : जयपुर सिटी/006/2023-25

न्यूज़ बेधड़क

सच बेधड़क

जयपुर, बुधवार, 24 जुलाई, 2024

निर्भय वही है जो सच के साथ है... जो झूठ का सहारा लेता है, वह हमेशा भय में रहता है।

विनायक शर्मा, फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ, सच बेधड़क मीडिया ग्रुप

दक्षिण गाजा के खान यूनिस इलाके में इजराइली सेना का हमला...

70 लोगों की मौत, 200 से अधिक घायल

एजेंसी । रफाह

इजराइल हमास के बीच पिछले एक साल से संघर्ष जारी है। इस बीच गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजराइल ने हमला किया, जिसमें 70 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 200 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमास नियंत्रित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। सेना ने चेतावनी दी कि वे इस इलाके में जबरन कार्रवाई करेंगे। सेना की तरफ से दी गई चेतावनी में दक्षिण गाजा में अल मवासी मानवीय क्षेत्र के पूर्वी खान यूनिस को प्रभावित किया, जिसके कारण हजारों फलस्तीनियों को इस क्षेत्र से भागना पड़ा था।

एक साल से जारी है संघर्ष

बता दें कि पिछले साल सात अक्तूबर को हमास के आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1,197 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में ज्यादातर इजराइली नागरिक ही थे। आतंकियों ने 251 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले आए थे। इजराइली सेना का कहना है कि 116 बंधक अभी भी गाजा में हैं, जबकि 44 की मौत हो चुकी है। इस हमले का जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइली सेना ने गाजा पर हमले करते हुए क्षेत्र की बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया। इस हमले में गाजा के 39,000 लोग मारे गए।

यह बोला स्वास्थ्य मंत्रालय

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, "आज सुबह से लेकर अब तक खान यूनिस इलाके में हमले हो रहे हैं। इस हमले में 70 लोग मारे गए, जबकि 200 से अधिक घायल हो गए।" इजराइली सेना ने मृतकों की संख्या पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि, एक बयान में सेना ने बताया कि उनके फाइटर जेट और टैंक ने इस क्षेत्र में आतंकियों ठिकानों पर हमला कर उनका सफाया किया। बयान में बताया गया कि सेना ने खान यूनिस के 30 से अधिक आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इजराइली सेना ने हमास आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हथियार भंडारण सुविधा, सुरंग शाफ्ट और संरचनाओं को भी निशाना बनाया।

गाजा के खान यूनिस क्षेत्र में हमला

इस साल की शुरुआत में ही खान यूनिस में कई बार हमले किए गए। ताजा घटना स्वास्थ्य मंत्रालय के उस बयान के नौ दिन बाद की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अल-मवासी में किए गए हमले में 92 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने कहा कि वह हमास के कमांडर को निशाना बना रहे थे। इजराइल ने हमास को पूरी तरह से नष्ट करने की कसम खाई थी। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है।

नेतन्याहू मिलेंगे बाइडेन से

नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। बाइडेन लगातार इजराइली राष्ट्रपति से युद्ध विराम को लेकर बात कर रहे हैं। पिछले साल सात अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले के नौ महीने बाद भी इजराइल-हमास के बीच संघर्ष जारी है। इस साल जून में नेतन्याहू ने कहा था कि युद्ध अपने तीव्र चरण पर है और खत्म होने वाला है।

इथियोपिया में भूस्खलन: भारी बारिश के बीच धंस गई जमीन

कम से कम 146 मरे

एजेंसी । अदिस अबाबा

इथियोपिया के एक दूरस्थ गोफा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 146 लोगों की मौत हो गई है। एक स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी। स्थानीय प्रशासक दागमावी आयेले ने बताया कि दक्षिणी इथियोपिया के केंचो शाचा गोजदी जिले में गोफा इलाके में मिट्टी धंसने की घटना में मारे गए लोगों में बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं।

ज्यादातर लोग सोमवार सुबह हुए भूस्खलन में दब गए, जब बचावकर्मी एक दिन पहले हुए एक अन्य भूस्खलन के बाद पीड़ितों की तलाश कर रहे थे। आयेले ने बताया कि मलबे से पांच लोगों को जीवित निकाला गया। उन्होंने बताया, 'कई बच्चे हैं जो हादसे में अपनी मां, पिता, भाई और बहन समेत पूरे परिवार को खो चुके हैं तथा लाशों से लिपट रहे हैं।' बचाव अभियान जारी रहने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इथियोपिया में जुलाई में शुरू होने वाले बारिश के मौसम में भूस्खलन होना आम है। बारिश का यह मौसम सितंबर मध्य तक जारी रहने की संभावना है।

हताहतों में एक अधिकारी भी शामिल

गोफा क्षेत्र के सामान्य प्रशासक मेस्किर मिटकू ने कहा कि हताहतों में महिलाएं, बच्चे और पुलिस अधिकारी शामिल हैं। गोफा जिले के सरकारी प्रवक्ता कसाहुन अबायनेह ने कहा, रविवार रात को भारी बारिश हुई और भूस्खलन से कुछ लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गोफा दक्षिणी इथियोपिया के नाम से जाने जाने वाले राज्य का हिस्सा है, जो राजधानी अदीस अबाबा से लगभग 320 किमी दूर स्थित है।

गोफा क्षेत्र में दो दिन में दो दुखांतिका

माना जा रहा है कि गोफा क्षेत्र के एक सुदूर पहाड़ी इलाके में भारी बारिश के बाद रविवार शाम और सोमवार सुबह दो घटनाएं हुईं। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि जीवित बचे लोगों की तलाश "जोरदार तरीके से जारी है, लेकिन "मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। हादसे के बाद सैकड़ों लोग घटनास्थल पर एकत्र हुए थे और अन्य लोग नीचे फंसे लोगों की तलाश में मिट्टी खोदते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां

अब हिंदू मंदिर को बनाया निशाना

एजेंसी । टोरंटो

कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ बनता जा रहा है। खालिस्तान समर्थकों का गढ़ बन चुके कनाडा में इन तत्वों के खिलाफ एक्शन न लेकर प्रशासन इनको बढ़ावा दे रहा है। इस कड़ी में सोमवार को कनाडा के एडमोंटन में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया।

मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी टिप्पणियां लिख दी गईं। सोमवार को हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने बताया कि BAPS स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। साथ ही कहा कि ग्रैफिटी के जरिए भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य पर भी हमला किया गया।

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने की पुष्टि

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने X पर एक पोस्ट के जरिए घचना की जानकारी दी। पोस्ट में संगठन ने लिखा, "@chcconline पुष्टि कर रहा है कि कनाडा के एडमोंटन में @BAPS मंदिर सोमवार सुबह एक और हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। मंदिर पर कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ हिंदू सदस्यों में से एक @AryaCanada के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया। हम इस घटना की निंदा करते हैं, इसके लिए खालिस्तान समर्थक दोषी हैं।"

एक्शन की उठी मांग

कनाडा में सांसद सांसद चंद्र आर्य ने X पर पोस्ट में कहा, "जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं, खालिस्तानी चरमपंथी हिंसा फैलाने के बावजूद आसानी से बच जाते हैं। हिंदू कनाडाई इससे चिंतित हैं। मैं फिर से कनाडा की कानूनी एजेंसियों से इसको गंभीरता से लेने की गुजारिश करता हूं, इससे पहले कि ये बयानबाजी लोगों के खिलाफ शारीरिक हिंसा में तब्दील हो जाए।" कनाडा के प्रशासन से इन खतरों से निपटने और कनाडा में सभी धार्मिक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

सृष्टिविनायक एंटरटेनमेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक मिताली यादव द्वारा सच बेधड़क दैनिक हिन्दी अखबार, 34/16-ए, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर-302020 (राजस्थान) से प्रकाशित एवं भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, शिवदासपुरा, रेलवे क्रॉसिंग टोंक रोड, जयपुर (राजस्थान) से मुद्रित।
संपादक: विनायक शर्मा*, **फोन नं. :** 9664014179 (ऑफिस), **ई-मेल:** news@sachbedhadak.com, **RNI No. :** RAJHIN/2021/82557 *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार।

दैनिक हिन्दी अख़बार

सच बेधड़क

"सच बेधड़क" दैनिक हिन्दी अख़बार की प्रति PDF के माध्यम से मुफ़्त प्राप्त करने के लिए इस लिंक पर Click कीजिए

Telegram

https://rb.gy/3bkrnl